सूर्योदय - 06:26
सूर्यास्त - 05 : 44

अधिकतम तापमान 32.0°
न्यूनतम तापमान 19.0°

ओपन सर्च

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

RNI No.DELHIN/2015/66886

खबरें और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें

Mob. : 9210092542
opensearchnews@gmail.com

E-mail | opensearchdelhi@gmail.com
Facebook | https://www.facebook.com/opensearch.co.in
Website | www.opensearch.co.in

वर्ष : 12 अंक : 352 नई दिल्ली, गुरूवार 26 नवम्बर-2026
नई दिल्ली, हरियाणा, बिहार से प्रकाशित
` मूल्य : 02 रूपए | पृष्ठ : 08

कैबिनेट ने 11,000 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी

निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली.एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 'स्कीम फॉर एन्हांसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट (सीआईई) मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम' को मंजूरी दे दी। 11,000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान वाली इस योजना का उद्देश्य भारत में निर्माण और अवसंरचना उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती प्रदान करना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक बयान के अनुसार, इस योजना को भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य निर्माण एवं अवसंरचना उपकरणों (कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्यूपमेंट-सीआईई) और उनके कंपोनेंट्स के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा देश में एक समर्पित परीक्षण सुविधा स्थापित करना है।

इससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और वैश्विक सीआईई बाजार में उसकी स्थिति मजबूत होगी। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से आठ वर्षों के लिए लागू होगी, जिसमें पहले दो वर्ष (2026-27 से 2027-28) विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए होंगे। इसके बाद पांच वर्षों (2028-29 से 2032-33) तक प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी। अंतिम वर्ष 2033-34 में 2032-33 की अतिरिक्त बिक्री के आधार पर प्रोत्साहनों का निपटान किया जाएगा। बयान में कहा गया कि योजना के दो प्रमुख घटक हैं।

पहले घटक के तहत पात्र निर्माण उपकरण निर्माताओं और कंपोनेंट निर्माताओं को अतिरिक्त बिक्री के आधार पर सेल्स-लिंक्ड इंसेंटिव (एसएलआई) प्रदान किया जाएगा।



11,000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान वाली इस योजना का उद्देश्य भारत में निर्माण और अवसंरचना उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक बयान के अनुसार, इस योजना को भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा लागू किया जाएगा

कैबिनेट ने असम में 2,014 करोड़ रुपए की लागत से डोलू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को असम के सिलचर के निकट डोलू में एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा विकसित की जाने वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,014 करोड़ रुपये होगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा सिलचर हवाईअड्डे पर मौजूद परिचालन और भूमि संबंधी सीमाओं को दूर करना तथा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही हवाई यात्रा की मांग को पूरा करना है।

वर्तमान सिलचर हवाईअड्डा रक्षा भूमि से घिरे एक सिविल एन्क्लेव के रूप में संचालित होता है, जिसके विस्तार की सीमित संभावनाएं हैं। कछार जिले में स्थित डोलू को बराक घाटी का रणनीतिक



केंद्र माना जाता है, जो अपने चाय बागानों, कृषि आधारित उद्योगों और इको-टूरिज्म तथा सांस्कृतिक पर्यटन की संभावनाओं के लिए जाना जाता है। प्रस्तावित हवाईअड्डे में 12,351 वर्गमीटर क्षेत्रफल का आधुनिक टर्मिनल भवन बनाया जाएगा, जो पीक आवर्स में 800 यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगा। टर्मिनल को आधुनिक सुविधाओं, हरित भवन (ग्रीन बिल्डिंग) सिद्धांतों और भविष्य में विस्तार की क्षमता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा। परियोजना के तहत 2,705 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे विकसित किया जाएगा, जो कोड-4सी मानकों के अनुरूप होगा।

मजबूत सुधारों और निवेश से आकार ले रहा विकसित भारत 2047 : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली.एजेंसी



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत की आर्थिक क्षमता को स्थायी समृद्धि में बदलने के लिए सरकार और उद्योग जगत को 'टीम भारत' के रूप में मिलकर काम करना चाहिए। आर. मुकुंदन ने एक प्रमुख वित्तीय दैनिक समाचार पत्र में एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने कल्पना की है कि अगस्त 2047 में, भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष पर, सीआईआई (भारतीय उद्योग परिसंघ) के अध्यक्ष क्या लिखेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि विकसित भारत 2047 यात्रा मजबूत सुधारों और मुख्य सेक्टर्स में निवेश से आकार ले रही है। पीएमओ इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर. मुकुंदन के एक लेख का जिक्र किया। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे बुनियादी ढांचे में निवेश, जीएसटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट टैक्स में सुधार, पीएलआई योजनाओं और व्यापार समझौतों के जरिए विकास की नींव रखी गई है। पोस्ट में आगे कहा कि भारत की आर्थिक क्षमता को स्थायी समृद्धि में बदलने के लिए सरकार और उद्योग जगत को 'टीम भारत' के रूप में मिलकर काम करना चाहिए। आर. मुकुंदन ने एक प्रमुख वित्तीय दैनिक समाचार पत्र में एक लेख लिखा।

इसमें उन्होंने कल्पना की है कि अगस्त 2047 में, भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष पर, सीआईआई (भारतीय उद्योग परिसंघ) के अध्यक्ष क्या लिखेंगे। साथ ही, उन्होंने एक 'विकसित भारत' तक पहुंचने के लिए जरूरी रोडमैप भी पेश किया है। मुकुंदन भारत को एक उच्च-आय वाले देश के रूप में देखते हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग का कुल उत्पादन में 25 प्रतिशत योगदान हो, औपचारिक रोजगार और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, और भारतीय कंपनियां सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में अग्रणी हों। वर्तमान आर्थिक पैमानों का जिक्र करते हुए, मुकुंदन ने कहा कि 2025 तक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) 2,760 डॉलर थी, विनिर्माण का जीवीए (सकल मूल्य वर्धन) में योगदान लगभग 15 प्रतिशत था, और आरएंडडी (अनुसंधान और विकास) पर खर्च जीडीपी का 0.84 प्रतिशत था। लेख में आगे बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन गए। इस दौरान सेमीकंडक्टर से जुड़ी 12 परियोजनाओं को मंजूरी मिली, गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट के पार पहुंच गई, और अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच घोषित 26.6 लाख करोड़ की परियोजनाओं में 86 प्रतिशत निवेश निजी क्षेत्र से आया।

इसमें आगे कहा कि जीएसटी सुधारों, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, बुनियादी ढांचे में निवेश और पीएलआई (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन) योजनाओं की मदद से भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत के स्तर पर बनी रही।

आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत



नई दिल्ली.एजेंसी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए हाईकोर्ट वापस भेज दिया है। अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में पक्षकार के रूप में शामिल करने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें इस मामले में लगे आरोपों की सीबीआई और ईडी से जांच कराने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट ने यह आदेश भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की याचिका पर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामला वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया।

कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि वो इस मामले में नए सिरे से विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को राहुल गांधी का पक्ष सुने बिना आदेश नहीं देना चाहिए था। बता दें कि कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया था और केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच की मांग की थी। 12 मई 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा था कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायत एजेंसियों को मिली है, तो आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन किया जाए और सीबीआई व प्रवर्तन निदेशालय कानून के तहत उचित कदम उठा सकते हैं। इसके बाद 20 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट ने सीबीआई के हलफनामे पर असंतोष जताया था और आगे की प्रगति व रिपोर्ट मांगी थी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भुवनेश्वर में होम्योपैथी पर आयोजित राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन में हुई शामिल

भुवनेश्वर.एजेंसी



हमारे संस्थानों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को सुलभ, न्यायपूर्ण, वैज्ञानिक दृष्टि से उत्तरदायी और संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने की दिशा में योगदान करना चाहिए : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मु ओडिशा के भुवनेश्वर में होम्योपैथी पर आयोजित राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन में शामिल हुईं। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि होम्योपैथी भारत की विविधतापूर्ण स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। समय बीतने के साथ-साथ, देश में इसका व्यापक संस्थागत विस्तार हुआ है और शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों तथा जनस्वास्थ्य नेटवर्क के माध्यम से यह लोगों को सुलभ हुई है।

राष्ट्रपति ने इस बात पर बल दिया कि होम्योपैथी की भावी विश्वसनीयता और अकादमिक प्रतिष्ठा काफी हद तक इसके अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रामाणिकता और उससे प्राप्त होने वाले नैदानिक साक्ष्यों की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। उन्होंने अनुसंधान संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक संगठनों से अनुसंधान की सुदृढ़ संस्कृति विकसित करने के लिए मिलकर कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी पर राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन सार्थक अकादमिक संवाद, संस्थागत साझेदारी और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण विकसित करने का एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों, विशेष रूप से युवा शोधकर्ताओं और पेशेवरों को इस बात की सलाह दी कि वे इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं।

राष्ट्रपति ने कहा कि होम्योपैथी के विकास के साथ-साथ वैज्ञानिक अनुसंधान, शैक्षणिक उत्कृष्टता और पेशेवर जवाबदेही के प्रति अटूट प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। अनुसंधान कार्य उचित कार्यपद्धति, समुचित रूप से तैयार किए गए नैदानिक अध्ययनों, सुव्यवस्थित दस्तावेजीकरण और पारदर्शी रिपोर्टिंग पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने बहुकेंद्रित अध्ययनों, व्यवस्थित समीक्षाओं, साक्ष्यों के विश्लेषण एवं मौलिक अनुसंधान तथा विश्वसनीय नैदानिक डेटाबेस के विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि अनुसंधान की सीमाओं को स्वीकार करने, प्रतिकूल निष्कर्षों को भी सामने रखने और निष्कर्षों को वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुरूप निर्धारित करने के लिए बौद्धिक ईमानदारी का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा का पेशा केवल शैक्षणिक योग्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए बौद्धिक अनुशासन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ईमानदारी, समानुभूति और जीवन भर सीखते रहने की प्रतिबद्धता भी आवश्यक है।

दिल्ली को सौगात : राजधानी में दो नए अस्पताल अगले साल होंगे शुरू, 40 आरोग्य मंदिर भी खुलेंगे

नई दिल्ली.ओपन सर्च



दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अगले साल दो नए अस्पताल शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही अगले महीने 40 और आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक कर अस्पतालों और स्वास्थ्य परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं का काम निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए चल रहे कार्यों में किसी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। दो नए अस्पतालों के शुरू होने से दिल्ली में मरीजों के लिए इलाज की सुविधाओं और अस्पतालों की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। वहीं, अगले महीने 40 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू होने से लोगों को उनके घरों के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ समयसीमा का भी विशेष ध्यान रखा जाए।

अधिकारी सीएम अनाउंसमेंट्स को पूरा करने में लाएं तेजी : नायब सैनी



कदम सिंह/ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान की गई मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयावधि में पूरे करवाए जाएं ताकि जनता को इनका समुचित लाभ मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

- मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में नायब सैनी ने दिए विशेष निर्देश
- अब तक की गई 7988 में से 5743 मुख्यमंत्री घोषणाएं पूरी, 1101 पर तेजी से चल रहा कार्य

बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी तथा खेल मंत्री गौरव गौतम सहित अनेक विधायक उपस्थित रहे। नायब सैनी ने कहा कि घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में संबंधित विभागों और विधायकों के बीच बेहतर समन्वय बेहद महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से विधायकों के साथ घोषणाओं की प्रगति का आकलन किया जा रहा है, ताकि लंबित विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके और उनके क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं का समाधान सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के दौरों के दौरान अब तक कुल 7988 घोषणाएं की गई हैं।

उत्तराखंड : सीएम धामी ने 36 नवनियुक्त नायब तहसीलदारों को सौंपे नियुक्ति पत्र

देहरादून.एजेंसी



उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सीएम आवास में 36 नवनियुक्त नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने 36 चयनित अभ्यर्थियों में 13 बेटियों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सफलता सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रही प्रदेश की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी।

सीएम ने कहा कि नवनियुक्त अधिकारियों की इस उपलब्धि के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ ही उनके माता-पिता एवं गुरुजनों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र के साथ ही आप सभी को जनसेवा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नायब तहसीलदार राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके कार्यों का सीधा संबंध आमजन की भूमि, आजीविका और अधिकारों से है। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से नामांतरण, पैमाइश, सीमांकन एवं राजस्व अभिलेखों से जुड़े मामलों का पूरी सावधानी, संवेदनशीलता और समयबद्धता के साथ निस्तारण करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि एक किसान के लिए उसकी भूमि परिवार की आजीविका और बच्चों के भविष्य का आधार होती है। अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण के निस्तारण में इससे जुड़े परिवारों की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि तहसील में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनें तथा आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से तहसीलों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में जनजातीय क्षेत्रों में मजबूत हो रही सड़क संपर्क व्यवस्था

ओपन सर्च. संवाददाता



बगीचा विकासखंड में पांच वृहद पुलों का होगा निर्माण, ग्रामीणों को वर्षभर मिलेगी सुगम आवागमन की सुविधा शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजार तक पहुंच होगी आसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के दूरस्थ एवं जनजातीय बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सड़क संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत जशपुर जिले को पांच वृहद पुलों के निर्माण की सौगात मिली है।

राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इन पुलों के निर्माण के लिए कुल 16 करोड़ 3 लाख 34 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के बैच-I में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 6 नवंबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ में 167 पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के पांच वृहद पुल शामिल हैं। इन पुलों के निर्माण से विशेष रूप से दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी तथा ग्रामीण बसाहटों का मुख्य मार्गों से संपर्क मजबूत होगा। स्वीकृत कार्यों के तहत डंगरी से दरावाकोना मार्ग पर नाले में 60 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 3 करोड़ 56 लाख 23 हजार रुपये तथा जबला से नवापारा मार्ग पर नाले में 30 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 1 करोड़ 83 लाख 21 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसी प्रकार कमरीमा मंझाटोली से खपरीडीह मार्ग पर नाले में 60 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 4 करोड़ 4 लाख 19 हजार रुपये, बगीचा-कांसाबेल मार्ग से जनकपुर पहुंच मार्ग पर नाले में 80 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 3 करोड़ 52 लाख 67 हजार रुपये तथा कुहापानी से बांसधार मार्ग पर नाले में 60 मीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 3 करोड़ 7 लाख 4 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इन पुलों के निर्माण से वर्षा ऋतु में नालों के कारण आवागमन बाधित होने की समस्या से ग्रामीणों को राहत मिलेगी।

हरियाणा में वैश्विक निवेश को मिलेगी नई गति : मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा यूके और जर्मनी दौरे पर

ओपन सर्च ब्यूरो



- 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक प्रमुख उद्योगपतियों, वैश्विक निवेशकों, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ होंगी महत्वपूर्ण बैठकें

- व्यापार, निवेश, शिक्षा, कौशल विकास और एआई तकनीक पर सहयोग पर होगी चर्चा, जर्मनी में होगा हरियाणा का स्टेट रोड-शो

चंडीगढ़। हरियाणा में वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने और प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक एवं निवेश मानचित्र पर और अधिक सशक्त पहचान दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल 28 नवंबर से 5 दिसंबर, 2026 तक यूनाइटेड किंगडम (यूके) और जर्मनी के दौरे पर रहेगा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल प्रमुख वैश्विक कंपनियों, निवेशकों, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करेगा।

प्रतिनिधिमंडल में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहेंगे। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा सरकार प्रदेश को वैश्विक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में पहले भी मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जापान, सिंगापुर और स्वीडन का दौरा कर चुका है। इन दौरों के दौरान विभिन्न कंपनियों के साथ निवेश, औद्योगिक सहयोग और साझेदारी को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं और लगभग 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निवेश के लिए सहमति बनी है। इसी कड़ी में अब प्रतिनिधिमंडल यूनाइटेड किंगडम (यूके) और जर्मनी के दौरे पर जा रहा है। डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि यूके दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल विभिन्न बिजनेस लीडर्स, वैश्विक निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेगा। इसके अतिरिक्त, सी.आई.आई. के प्रतिनिधिमंडल के साथ भी हरियाणा में निवेश की संभावनाओं और औद्योगिक सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।

मुख्यमंत्री हरियाणा मूल के प्रवासी भारतीयों से भी संवाद करेंगे और उन्हें प्रदेश की विकास यात्रा से जुड़ने तथा हरियाणा में निवेश के माध्यम से राज्य की आर्थिक प्रगति में सहभागी बनने के लिए आमंत्रित करेंगे।

उन्होंने बताया कि 30 नवंबर और 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री विभिन्न प्रमुख उद्योगों, कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वन-टू-वन बैठकें करेंगे। इसके साथ ही भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार एवं निवेश की संभावनाओं को लेकर विशेष राउंडटेबल बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में शिक्षा, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत चर्चा होगी और विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री यूके के सांसदों एवं अन्य प्रमुख प्रतिनिधियों को हरियाणा आने तथा अप्रैल 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेंगे।

मुख्यमंत्री इस दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के सेंटर फॉर साइंस एंड पॉलिसी के प्रतिनिधियों के साथ भी संवाद करेंगे। इसके अलावा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में अध्ययनरत भारतीय विद्यार्थियों से संवाद कर उनके अनुभवों, विचारों और हरियाणा के विकास में उनकी संभावित भूमिका पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री क्वीन्स एलिजाबेथ स्कूल, बार्नेट का भी दौरा करेंगे, जहां शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और हरियाणा में शैक्षणिक कैंपस स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा। डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि लंदन में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का भी विशेष आयोजन किया जाएगा, जिसमें नायब सैनी विशेष रूप से हिस्सा लेंगे।

इस अवसर पर हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत और धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र के महत्ता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही, श्रीमद्भगवद्गीता के सार्वभौमिक संदेश–कर्म, कर्तव्य और मानव कल्याण–को विश्वभर में प्रसारित करने तथा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने पर विशेष बल दिया जाएगा। डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि जर्मनी दौरे के दौरान 2 दिसंबर को हरियाणा स्टेट रोड-शो आयोजित किया जाएगा।

15 दिसंबर को मुख्यमंत्री नायब सैनी तीर्थयात्रियों की ट्रैन को हरी झंडी दिखा कर करेंगे रवाना

ओपन सर्च ब्यूरो



मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्ग श्रद्धालुओं को निःशुल्क वाराणसी तीर्थ यात्रा करवाएगी हरियाणा सरकार, आवेदन के लिए खुला पोर्टल

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के बुजुर्ग श्रद्धालुओं को 15 दिसंबर को 4 दिवसीय निःशुल्क वाराणसी तीर्थ यात्रा करवाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस विशेष ट्रैन को हरीझंडी दिखाकर रवाना करेंगें। यात्रा के लिए पात्र श्रद्धालुओं से आवेदन आमंत्रित करने हेतु पोर्टल खोल दिया गया है।

इस संबंध में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक डॉ आदित्य दहिया ने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वो यथाशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन सरल पोर्टल पर https://saral-haryana.gov.in पर किया जा रहा है। डॉ आदित्य दहिया ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा आगामी दिनों में विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को वाराणसी के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रेल यात्रा के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु को पर्यटक किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना का लाभ 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्ग श्रद्धालु उठा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत इससे पहले प्रदेश के श्रद्धालुओं को अयोध्या तथा महाराष्ट्र स्थित श्री हजूर साहिब, नांदेड़ की निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जा चुकी है। योजना के तहत पात्रता के लिए श्रद्धालु के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

एसआईआर कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित करें अधिकारी : नेहा सिंह



ओपन सर्च ब्यूरो

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों के साथ की समीक्षा बैठक

सोनीपत। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा ए. श्रीनिवास ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ एसआईआर-2026 (विशेष गहन पुनरीक्षण) एएसडीडी मतदाताओं से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने एक-एक करके सभी जिलों के उपायुक्तों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में एएसडीडी मतदाताओं से संबंधित प्रक्रिया तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तैयारियों सहित विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि जिला सोनीपत में 30 नवंबर तक एएसडीडी मतदाताओं के गणना प्रपत्रों के वितरण एवं संग्रह का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा रहे हैं। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी एक बैठक आयोजित की जा चुकी है, ताकि एसआईआर प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि जिला में 211 ईएलसी (इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब) पंजीकृत हैं और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लिकेट) मतदाताओं से संबंधित प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित समय-सारणी के अनुसार 15 दिसंबर 2026 तक दावों एवं आपत्तियों के निपटान की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, जबकि 22 दिसंबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसआईआर से जुड़े सभी कार्य पूरी गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित करें। इस दौरान एडीसी अजय चोपड़ा, निर्वाचन तहसीलदार दिनेश शर्मा व सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

छपाई के बाद गणना प्रपत्र बीएलओ को वितरित, गणना प्रपत्रों का निपटारा 10 तक : डॉ. आनंद कुमार शर्मा

ओपन सर्च ब्यूरो



करनाल। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आनंद कुमार शर्मा के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत अथवा दोहरी प्रविष्टि की श्रेणी में रखे गए मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र प्रिंटिंग के बाद बीएलओ को वितरित किए जा चुके हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक आयोजित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर तक गणना प्रपत्रों का निपटारा कर दिया जाएगा।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त ए श्रीनिवास द्वारा एसआईआर को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि जिला में एएसडीडी मतदाताओं की कुल संख्या 210510 है। प्रपत्र छपाई के बाद संबंधित विधानसभा क्षेत्रों एवं मतदान केंद्रों के अनुसार संबंधित बीएलओ को वितरित कर दिए गए है। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अनुरोध किया गया है कि बीएलए के माध्यम से इस कार्य में सहयोग करें। बीएलए-2 की भूमिका एवं जिम्मेदारियों के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल ऐजेंटों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से पूरा करने के लिए बीएलए-2 से अनुरोध किया गया है कि संबंधित मतदान केंद्र के तहत एएसडीडी मतदाताओं की सूची एवं गणना प्रपत्रों से संबंधित कार्यों में बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित करें।

कर्ण स्टेडियम में जल्द बनेंगे 6 बैडमिंटन कोर्ट और बड़ा बॉक्सिंग हॉल : जगमोहन आनंद

गीता देवी/ओपन सर्च ब्यूरो



करनाल। विधायक जगमोहन आनंद ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री घोषणा समीक्षा बैठक में भाग लिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी विधायकों के साथ एसीएस स्तर एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की वन-टू-वन बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विधायक जगमोहन आनंद ने करनाल विधानसभा क्षेत्र से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं की लंबित मांगों एवं विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। विधायक जगमोहन आनंद ने बताया कि करनाल में लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और आने वाले समय में कई बड़ी विकास परियोजनाओं को भी धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से करनाल के कर्ण स्टेडियम के विकास का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं में खेलों के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है। हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि कर्ण स्टेडियम में जल्द ही 6 नए बैडमिंटन कोर्ट और एक बड़े बॉक्सिंग हॉल का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए ड्राइंग एवं एस्टीमेट संबंधित विभाग को भेजे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों एवं दर्शकों की सुविधा के लिए बैठने हेतु सीढ़ीनुमा स्टैंड (स्टेप्स) के निर्माण की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि करनाल को खेल सुविधाओं के क्षेत्र में और अधिक सशक्त बनाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास कार्यों को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही है। बैठक में उठाई गई सभी लंबित मांगों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है और उनका प्रयास रहेगा कि करनाल विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रस्तावित एवं लंबित विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए।

27 नवंबर तक एचटेट अभ्यर्थी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, 28 व 29 नवंबर को ऑनलाइन ही कर सकेंगे विवरणों में संशोधन

ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष डॉ0 शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2026 (एचटेट) लेवल-1, 2 व 3 का आयोजन 26 व 27 दिसंबर, 2026 को किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढक़र/समझकर 27 नवंबर, 2026 (रात्रि 11:59 बजे) तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं, परंतु अभी तक शुल्क जमा नहीं करवाया गया है, वे आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर, 2026 से पूर्व अपना शुल्क जमा करवाते हुए आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन आवेदन व परीक्षा शुल्क के सफलतापूर्वक जमा करने के बाद अभ्यर्थी पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंट लेना सुनिश्चित कर लें। श्री धूपड़ ने बताया कि एचटेट-2026 परीक्षा के लिए आवेदन 18 नवंबर, 2026 से लाईव किए जा चुके हैं। परीक्षा से संबन्धित सूचना बुलेटिन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है।

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सूचना बुलेटिन में दर्शाए गए महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढक़र/समझकर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी 28 व 29 नवंबर, 2026 को अपने विवरणों में ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। 27 नवंबर, 2026 उपरांत ऑनलाइन आवेदन तथा 29 नवंबर, 2026 उपरांत विवरण सुधार की अनुमति नहीं होगी। इस सन्दर्भ में कोई भी प्रार्थना पत्र/प्रतिवेदन किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

केवल घोषणाओं से नहीं होता खिलाड़ियों का सम्मान, समय पर मिले पुरस्कार राशि और सुविधाएं : कुमारी सैलजा



नकली दवाओं का कारोबार जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, सरकार उठाए कठोर कदम : सैलजा

कुमारी सैलजा ने गुरुग्राम में जब्त करीब 70 लाख रुपये के कथित नकली माउंजारो इंजेक्शन के सभी छह नमूने जांच में विफल पाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि निर्धारित 10 मिलीग्राम के मुकाबले अधिकतम 1.6 मिलीग्राम औषधि मिलना बेहद चिंताजनक है। जीवनरक्षक और उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की गुणवत्ता से समझौता किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। सरकार प्रदेशभर में दवाओं की नियमित जांच करवाए, नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री से जुड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करे तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे।

ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, कार्यसमिति की सदस्य कुमारी सैलजा ने हरियाणा में खिलाड़ियों को समय पर पुरस्कार राशि, खेल किट और यात्रा भत्ता नहीं मिलने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार खिलाड़ियों के सम्मान में बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो करती है, लेकिन उन्हें धरातल पर लागू करने में गंभीरता नहीं दिखाती। केवल घोषणाओं से खिलाड़ियों का सम्मान नहीं होता, इसके लिए उन्हें समय पर उनका हक देना जरूरी है। कुमारी सैलजा ने कहा कि रोहतक में आयोजित अंडर-14 राज्य स्तरीय स्कूली योग एवं हॉकी प्रतियोगिताओं के डेढ़ माह बाद भी 72 पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि नहीं मिली है। वहीं, करीब 840 खिलाड़ियों का यात्रा एवं दैनिक भत्ता अटका हुआ है तथा 620 खिलाड़ी अभी तक खेल किट का इंतजार कर रहे हैं।

प्रतियोगिता से पहले मिलने वाली खेल किट के लिए अब टेंडर प्रक्रिया अपनाया जाना विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा के अनेक खिलाड़ी अपने व्यक्तिगत प्रयासों, अभिभावकों की मेहनत और सीमित संसाधनों के बल पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाते हैं। अनेक गांवों में ग्रामीण और ग्राम पंचायतें मिलकर खिलाड़ियों की तैयारी में आर्थिक एवं अन्य सहयोग करती हैं।

इसके बावजूद सरकार पदक जीतने के बाद घोषित पुरस्कार राशि भी समय पर उपलब्ध नहीं करवा पाती। कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश के अनेक खेल मैदानों और स्टेडियमों में गुणवत्तापूर्ण खेल उपकरण, प्रशिक्षक तथा आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सरकार को खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए जमीनी स्तर पर निवेश करना चाहिए। सांसद ने मुख्यमंत्री से मांग की कि खिलाड़ियों की लंबित पुरस्कार राशि और भत्तों का तत्काल भुगतान किया जाए, खेल किट उपलब्ध करवाई जाए तथा प्रदेशभर के खेल मैदानों की स्थिति की समीक्षा कर सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

हरियाणा में आधार सेवाओं की पहुंच होगी और आसान, UIDAI ने 17 आधार सेवा केंद्र किए स्थापित

ओपन सर्च ब्यूरो



चंडीगढ़। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ द्वारा हरियाणा के नागरिकों को आधार सेवाएं सुगमता से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में 17 आधार सेवा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को आधार से संबंधित सेवाएं उनके नजदीक ही उपलब्ध हो रही हैं।

इससे नागरिकों को सामान्य आधार संबंधी कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। IDAI द्वारा स्थापित ये आधार सेवा केंद्र हिसार, गुरुग्राम, सोनीपत, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, भिवानी, पानीपत, मेवात (नूंह), जींद, झज्जर, करनाल, रोहतक और पलवल में स्थित हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य नागरिकों को आधार सेवाओं के लिए अतिरिक्त सुविधा और आसान पहुंच उपलब्ध करवाना है। नागरिक अपने निवास स्थान के नजदीक स्थित आधार सेवा केंद्र पर जाकर सुविधानुसार सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये केंद्र पहले से संचालित अन्य आधार नामांकन एवं अपडेट केंद्रों के अतिरिक्त सुविधा केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। हिसार का आधार सेवा केंद्र SCO-43, प्रथम तल, सेक्टर-13, मेन पार्किंग, तोशाम रोड, डाबचौक के नजदीक स्थित है।

वैभव सूर्यवंशी के तूफानी दोहरे शतक पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दी शुभकामनाएं

ओपन सर्च ब्यूरो



चंडीगढ़। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी द्वारा भारतीय-ए टीम के लिए यूएई के खिलाफ मात्र 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रचने पर उन्हें शुभकामनाएं दी और सूर्यवंशी को आने वाले क्रिकेट जगत का शंखनाद बताया। वहीं उन्होंने पंजाब में भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन को लेकर आप पार्टी द्वारा दिए गए बयान पर तीखा प्रहार करते हुए आप पार्टी को ही ठग बताया। विज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया में चमत्कार कर दिया है और छोटी उम्र में 52 गेंदों पर दोहरा शतक लगाकर तहलका मचा दिया है। उन्होंने कहा ये आने वाली क्रिकेट के भविष्य का शंखनाद है। वैभव सूर्यवंशी ने भारत का नाम रोशन कर दिया है और 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाओं से कई और नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। वैभव सूर्यवंशी को मंत्री अनिल विज ने शुभकामनाएं दी।

'ठगी से हुआ था आम आदमी पार्टी का जन्म, पार्टी के गुरू केजरीवाल को उखाड़कर फेंका अब केजरीवाल के चेले भगवंत मान को पंजाब से उखाड़ फेंकेंगे' : मंत्री अनिल विज

भाजपा और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा दिए ठगों व अवसरवादी जैसे बयानों पर पलटवार करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि ठग कौन है यह सारी दुनिया जानती है। आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही ठगी से हुआ था। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन किया था और उनको भारी समर्थन मिला था लेकिन अन्ना हजारे जी ने कभी एक बार भी नहीं कहा कि वह राजनीतिक पार्टी बनाकर सुधार करना चाहते हैं लेकिन इन्होंने उनकी लोकप्रियता को ठगी से चुराकर और लोगों को जोड़कर अपनी पार्टी बना ली लेकिन बेईमानी का काम बार-बार नहीं चलता। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के गुरु अरविंद केजरीवाल को हमने उखाड़कर फेंक दिया है और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी केजरीवाल के चेले भगवंत मान को भी उखाड़ कर फेंक देंगे।

रेणु बाला गुप्ता ने निगम कार्यालय में की जन सुनवाई, नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के दिए निर्देश

ओपन सर्च ब्यूरो



करनाल। नगर निगम महापौर रेणु बाला गुप्ता ने निगम कार्यालय में जन सुनवाई कर शहरवासियों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से सुना। जन सुनवाई में पहुंचे नागरिकों ने सीवरेज निकासी, पेयजल आपूर्ति, साफ-सफाई, प्रॉपर्टी आई.डी., सड़कों एवं गलियों की मरम्मत सहित विभिन्न नागरिक सुविधाओं से संबंधित समस्याएं महापौर के समक्ष रखीं। महापौर ने प्रत्येक शिकायत को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समस्याओं का उचित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करवाया गया, जबकि अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

नागरिकों की शिकायतों पर अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश

जन सुनवाई के दौरान महापौर ने संबंधित शाखाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने कार्यालय में बुलाकर शिकायतों की स्थिति पर चर्चा की और समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की शिकायतों को केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका वास्तविक समाधान सुनिश्चित करना निगम अधिकारियों की जिम्मेदारी है। प्रत्येक शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित शाखा समय रहते कार्रवाई करे और शिकायतकर्ता को समाधान के संबंध में उचित जानकारी भी उपलब्ध करवाए।

मूलभूत सुविधाओं में नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए

महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरवासियों को मूलभूत सुविधाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सीवरेज व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, शहर की सफाई, प्रॉपर्टी आई.डी. से संबंधित कार्य तथा सडक़ों और गलियों की मरम्मत जैसे जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। जहां भी कोई समस्या सामने आती है, वहां संबंधित अधिकारी तुरंत स्थिति का जायजा लेकर आवश्यक कार्रवाई करें और कार्य को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें।

जन शिकायतों के निस्तारण में जवाबदेही और तत्परता जरूरी

महापौर ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना और उनकी समस्याओं का सरल, सुगम एवं समयबद्ध समाधान करना है। जन सुनवाई नागरिकों और नगर निगम के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिससे शहर की वास्तविक समस्याओं की जानकारी मिलती है और उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं।

उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों पर नियमित निगरानी रखें, समाधान में तेजी लाएं तथा जनहित से जुड़े कार्यों में जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। महापौर रेणु बाला गुप्ता ने स्पष्ट किया कि शहरवासियों की सुविधा और समस्याओं का समाधान नगर निगम की प्राथमिकता है।

दिल्ली-एनसीआर में ठंड और प्रदूषण का दोहरा प्रहार : घने कोहरे का अलर्ट, एक्यूआई लाल जोन में

नई दिल्ली (एजेंसी)



राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। ठंड तेजी से बढ़ रही है और सुबह-शाम की ठिठुरन ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। खासकर 26 और 27 नवंबर के आसपास घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे दृश्यता और यातायात प्रभावित होने की संभावना है।

उत्तर-पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के असर से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के डेटा के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते तापमान में हल्के उतार-चढ़ाव के बाद आगे और गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, 25, 26 और 27 नवंबर को एनसीआर में 'शैलो फॉग' यानी हल्के कोहरे का प्रभाव रहेगा। हालांकि, 28, 29 और 30 नवंबर तक कोहरा और गहरा सकता है। मौसम में आए इस बदलाव के साथ ही दिल्ली-एनसीआर की हवा भी जहरीली होती जा रही है। लगातार 10 दिनों तक 'ऑरेंज जोन' में रहने के बाद अब एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'लाल निशान' यानी खराब से बहुत खराब श्रेणी के पार पहुंच गया है।

प्रदूषण के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और अन्य एजेंसियों के स्टेशनों पर दर्ज एक्यूआई के अनुसार, आनंद विहार की हवा सबसे ज्यादा खराब है, एक्यूआई 348 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में है। बुराड़ी क्रॉसिंग में 305, बवाना में 261, आया नगर में 249, आशोक विहार में 223 और अलीपुर में 219 एक्यूआई दर्ज किया गया है। एनसीआर के अन्य शहरों की बात करें तो नोएडा में भी प्रदूषण ने पैर पसार लिए हैं।

नोएडा के सेक्टर-62 में 346, सेक्टर-143 में 299, सेक्टर-116 में 213 और सेक्टर-125 में एक्यूआई 199 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में हालात बेहद चिंताजनक हैं। वेद विहार-लोनी में एक्यूआई 349 है। गोविंदपुरम में 279, वेव सिटी में 264, न्यू तहसील-लोनी में 238 और दसना देहात में 235 एक्यूआई दर्ज किया गया है। वसुंधरा (217), लोनी (212), संजय नगर (206) और इंदिरापुरम (181) की हवा भी खराब श्रेणी में ही है।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'खराब', सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा छाए रहने की संभावना

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में प्रदूषण का स्तर ऊंचा बना हुआ है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बुधवार सुबह भी 'खराब' श्रेणी में बनी रही। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के अनुसार, सुबह छह बजे तक शहर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 228 दर्ज किया गया। यह स्तर 'खराब' श्रेणी में आता है, जो सामान्य लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। शहर के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (डीटीयू) सबसे ऊपर रहा, जहां एक्यूआई 331 दर्ज किया गया।

इसके बाद आनंद विहार में 327 और नॉर्थ कैंपस में 314 का एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। वहीं, इग्नू-मैदानगढ़ी और बुराड़ी क्रॉसिंग में वायु गुणवत्ता सूचकांक 304-304 दर्ज किया गया। अशोक विहार में भी वायु गुणवत्ता चिंताजनक रही और यहां एक्यूआई 224 दर्ज किया गया। इस बीच, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अनुमान जताया है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और बारिश नहीं होगी। सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिन का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आईएमडी ने 25 और 26 नवंबर को इस क्षेत्र में कई जगहों पर धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है।

थानों में सुरक्षा के नियम?: जामा मस्जिद हमले ने खोली पुलिस व्यवस्था की पोल, पुलिसकर्मियों ने क्या कहा

नई दिल्ली (एजेंसी)



आम जनता की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पुलिस खुद कितनी सुरक्षित है, क्या थानों में तैनात पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस नियम और व्यवस्था है, अगर किसी थाने में कोई व्यक्ति कमर में चाकू छिपाकर दाखिल हो जाए और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दे, तो वहां मौजूद कर्मी अपनी सुरक्षा कैसे करें।

जामा मस्जिद थाने में पुलिसकर्मियों पर हुए चाकू से हमले ने इन सवालों को एक बार फिर सामने ला दिया है। विडंबना यह है कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए दिन-रात मुस्तैद रहने वाली पुलिस की अपनी सुरक्षा थानों के भीतर सवालों के घेरे में है। पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि थानों में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच के लिए क्या कोई एक समान और प्रभावी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू है। फिलहाल थानों की सुरक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर संतरी होता है। वह संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। क्या हर थाने में मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड स्कैनर और तलाशी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। पुलिसकर्मियों का कहना है कि थानों के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए जाने चाहिए। थाने में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद ही प्रवेश दिया जाए। इसके अलावा हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से भी संदिग्ध लोगों की जांच की जा सकती है। थाने के भीतर अचानक होने वाले हमले से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों के पास क्या इंतजाम होने चाहिए, यह भी बड़ा सवाल है। पुलिस कर्मियों का कहना है कि थानों में तैनात कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी और जोखिम के अनुरूप सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस : सिर्फ एक दिन नहीं, रोजाना निभाएं धरती बचाने की जिम्मेदारी

नई दिल्ली (एजेंसी)



हर साल 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जिस धरती पर हम रहते हैं, वह सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी करने का जरिया नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। साफ हवा, पीने का पानी, हरे-भरे जंगल, उपजाऊ मिट्टी और प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। लेकिन अपनी सुविधाओं और जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में हम लगातार प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं पहले से कहीं ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं। कहीं जंगल तेजी से काटे जा रहे हैं, तो कहीं नदियां और समुद्र प्रदूषित हो रहे हैं। शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है। वहीं, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। कभी बेमौसम बारिश, कभी भीषण गर्मी तो कभी सूखे जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। ये सभी संकेत हैं कि अगर हमने समय रहते प्रकृति की देखभाल नहीं की, तो आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और उन्हें इसकी सुरक्षा के लिए प्रेरित करना है।

पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना सिर्फ सरकार या किसी सामाजिक संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें हर व्यक्ति की भूमिका अहम है। जब तक आम लोग अपनी आदतों में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक पर्यावरण को सुरक्षित रखना मुश्किल होगा। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों की ओर से पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, जागरूकता रैली, भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताओं जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन गतिविधियों के जरिए बच्चों और युवाओं को समझाया जाता है कि प्रकृति की रक्षा करना उनके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम करने या लाखों रुपये खर्च करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत हम अपने घर से ही कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रश करते समय नल खुला न छोड़ें, जरूरत न होने पर लाइट और पंखे बंद रखें और पानी की बर्बादी रोकें। इसके अलावा, बाजार जाते समय कपड़े या जूट का थैला साथ रखें, ताकि प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कम हो।

अमेजन ने भारत से कुल ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट में पार किया 27 अरब डॉलर का आंकड़ा, 2.4 लाख निर्यातकों को मिला वैश्विक बाजार

नई दिल्ली (एजेंसी)



अमेजन ने बुधवार को कहा कि उसके प्रमुख निर्यात कार्यक्रम अमेजन ग्लोबल सेलिंग के माध्यम से भारत से होने वाला कुल ई-कॉमर्स निर्यात 27 अरब डॉलर के स्तर को पार कर गया है। कंपनी ने कहा कि भारतीय निर्यातकों की बढ़ती भागीदारी और वैश्विक बाजारों में 'मेड इन इंडिया' उत्पादों की मजबूत मांग इस उपलब्धि के प्रमुख कारण हैं। वर्ष 2015 में शुरू किए गए अमेजन ग्लोबल सेलिंग कार्यक्रम के जरिए भारतीय व्यवसाय अमेजन के अंतरराष्ट्रीय मार्केटप्लेस पर अपने उत्पाद बेच सकते हैं।

पिछले 11 वर्षों में इस प्लेटफॉर्म से 2.4 लाख से अधिक भारतीय निर्यातक जुड़े हैं और उन्होंने दुनिया भर के ग्राहकों को 1 अरब से अधिक मेड-इन-इंडिया उत्पाद बेचे हैं। कंपनी ने बताया कि पिछले एक वर्ष के दौरान उसके निर्यातक आधार में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में भारत के 28 राज्यों, 7 केंद्रशासित प्रदेशों और 200 से अधिक शहरों एवं कस्बों के विक्रेता इस मंच का उपयोग कर रहे हैं। इन भारतीय विक्रेताओं को अमेजन के 18 से अधिक अंतरराष्ट्रीय स्टोर्स तक पहुंच प्राप्त है, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं। अमेजन ग्लोबल सेलिंग इंडिया के प्रमुख श्रीनिधि कालवापुडी ने कहा, भारत के पास वैश्विक उपभोक्ता निर्यात क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनने की क्षमता है और ई-कॉमर्स इस लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

जेईई मेन के लिए अब तक 15.69 लाख आवेदन, 26 नवंबर तक मिलेगा मौका

नई दिल्ली (एजेंसी)



जेईई मेन 2027 के पहले सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द समाप्त होने वाली है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के अनुसार, अब तक 15 लाख से अधिक फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। छात्र अभी आवेदन कर सकते हैं और यह आवेदन करने का अंतिम मौका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक, जेईई मेन के लिए कुल 15,69,514 आवेदन फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। इनमें से 13,92,344 अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क का भुगतान भी पूरा कर लिया है। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का मौका 26 नवंबर तक है। एनटीए ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना अपना आवेदन पूरा कर लें। आवेदन प्रक्रिया जेईई मेन एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी की जा सकती है। अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म भरने के साथ शुल्क भुगतान की प्रक्रिया भी निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी करनी होगी। गौरतलब है कि जेईई मेन देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है।

इसके जरिए अभ्यर्थियों को विभिन्न इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अवसर मिलता है। आवेदन या शुल्क भुगतान से जुड़ी किसी समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थी एनटीए की हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 और 1800-180-4747 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि (विलंब शुल्क सहित) 26 नवंबर है। वहीं, आईआईटी में प्रवेश पाने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए जेईई एडवांस्ड की परीक्षा आयोजित की जाती है। जेईई एडवांस्ड 2027 की परीक्षा 23 मई (रविवार) को आयोजित की जाएगी। छात्र इस परीक्षा में ऑन-स्क्रीन बेसिक कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली ने हाल ही में यह आधिकारिक घोषणाएं की हैं। इस बार आईआईटी दिल्ली जेईई एडवांस्ड 2027 का आयोजन करने वाला संस्थान है। छात्रों की सुविधा के लिए आईआईटी दिल्ली ने परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट भी शुरू कर दी है। इस वेबसाइट पर परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए पात्रता मानदंड उपलब्ध कराए गए हैं। वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थी जेईई एडवांस्ड 2027 में शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण शर्तों की पूरी जानकारी ले सकते हैं।

'हमारा गठबंधन जनता के साथ': भाजपा-अकाली गठबंधन पर केजरीवाल बोले- ये लोग सत्ता के लिए कभी एक साथ आ जाते हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने फिर से गठबंधन कर लिया है। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की मौजूदगी में गठबंधन का एलान किया। भाजपा और अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी ने दोनों दलों पर निशाना साधा है।

गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम लोगों का गठबंधन तो पंजाब की जनता साथ है। ये लोग सत्ता के लिए कभी एक साथ आ जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, और फिर दोबारा साथ आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम पंजाब के विकास के लिए काम कर रहे हैं। पूरा पंजाब देख सकता है कि पिछले पांच वर्षों में भगवंत मान ने चीजों को ठीक करने के लिए कितनी लगन से काम किया है, ताकि पिछले 70-75 वर्षों में पंजाब को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।' गठबंधन का एलान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'सभी को गुरु पर्व की बधाई। हमारे राष्ट्रीय साहब के नेतृत्व में आज अभी-अभी एक बैठक हुई है और उसमें अकाली दल और भाजपा के प्रमुख नेताओं ने बैठकर एक फैसला लिया है कि अगला पंजाब विधानसभा का चुनाव भाजपा और अकाली दल दोनों मिलकर लड़ेंगे और आज से अकाली दल एनडीए के साथी के रूप में राजनीति में काम करेंगे।

शाह ने कहा, यह बहुत खुशी की बात है कि एनडीए का सबसे पुराना सहयोगी, शिरोमणि अकाली दल आज फिर से एनडीए में वापस आ रहा है।

दिल्ली पुलिस ने चेन स्नेचिंग के मामले में एक आदतन अपराधी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)



दिल्ली पुलिस ने विशेष अभियान के दौरान चेन स्नेचिंग के मामले में एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को जानकारी दी कि इस अपराधी के खिलाफ 25 से अधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जिनमें स्नेचिंग, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट (हथियार कानून) से जुड़े मामले शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने न्यू अशोक नगर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए आदतन अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। यह कार्रवाई 27 अक्टूबर को मॉर्निंग वॉक के दौरान एक व्यक्ति की सोने की चेन छीनने की घटना के बाद की गई थी।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता विजय कुमार सेठ 27 अक्टूबर को सुबह लगभग 7 बजे, 'पार्वती विहार अपार्टमेंट' के पास मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने कथित तौर पर उनकी सोने की चेन और उसमें लगा 'ओम' का पेंडेंट छीन लिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद, न्यू अशोक नगर थाने में पुलिस ने बीएनएस की धारा 304(2)/3(5) के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पूर्वी जिले के एंटी-स्नैचिंग एंड बर्गलरी (एएसबी) सेल की एक विशेष टीम बनाई गई। जांच के दौरान, टीम ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्ध मोटरसाइकिल के आने-जाने के रास्तों का पता लगाया।

शिकायतकर्ता ने फुटेज में दिख रहे दो लोगों की पहचान उन संदिग्धों के रूप में की, जिन पर अपराध करने का आरोप है। शुरुआत में एएनपीआर फुटेज से पता चला कि मोटरसाइकिल पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर लगा था, वह जांच करने पर एक स्कूटर के नाम पर रजिस्टर्ड निकला। इससे साफ हुआ कि उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। रूट का पीछे की ओर विश्लेषण करते हुए, टीम ने संदिग्धों के आने-जाने के रास्ते का पता लगाया, जो न्यू अशोक नगर, कल्याणपुरी और नाला रोड से होकर गुजरता था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि संदिग्धों ने अपनी पहचान छिपाने और पकड़े जाने से बचने के लिए रास्ते में अपने कपड़े, हेलमेट, बैठने की स्थिति और मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बदल ली थी।

गाजीपुर अंडरपास के पास के एएनपीआर फुटेज की और जांच करने पर मोटरसाइकिल का असली रजिस्ट्रेशन नंबर सामने आया। इसके मालिक का पता लगाने और बाद में की गई फील्ड जांच की मदद से, पुलिस मोटरसाइकिल के मालिकाना हक तक पहुंचने और उससे जुड़े लोगों की पहचान करने में सफल रही।

जामा मस्जिद पुलिस अटैक : ड्रग्स-आतंकी एंगल से जांच, नौ पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपी नबील पर तीन एफआईआर

नई दिल्ली (एजेंसी)

जामा मस्जिद थाने के भीतर और चितली कबर इलाके में पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला करने के आरोपी नबील (30) के खिलाफ पुलिस ने तीन एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें दो मुकदमे जामा मस्जिद थाने में लूट और हत्या के प्रयास के आरोप में दर्ज किए गए हैं। वहीं, चितली कबर इलाके में पुलिस टीम पर हमले के मामले में चांदनी महल थाने में हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज हुई है।

दूसरी ओर, आरोपी की मां और बहन ने उनको परेशान करने की शिकायत की थी। पुलिस अब आरोपी की नशे की आदत और उसे मादक पदार्थ मुहैया कराने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसके तार किसी ड्रग्स तस्कर गिरोह से जुड़े हैं या नहीं। आतंकी कनेक्शन समेत अन्य संभावित पहलुओं को भी जांच के दायरे में रखा गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार को हुई इस वारदात में कुल नौ पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इनमें से तीन की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य घायल पुलिसकर्मियों का उपचार जारी है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि नबील को नशे की खेप कहां से मिलती थी और वह किन लोगों के संपर्क में था। इसके अलावा हमले में इस्तेमाल किए गए चाकू के स्रोत का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, नबील के खिलाफ वर्ष 2022 में दरियागंज थाने में भी एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। मध्य पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि नबील ने कमर के पास चाकू छिपा रखा था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि थाने में दाखिल होते समय उसकी तलाशी क्यों नहीं ली जा सकी।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला : मेले में छूट की बहार, आधी कीमत पर मिल रहे जैकेट-स्वेटर

नई दिल्ली (एजेंसी)



व्यापार मेले में छूट की बहार आ गई है। दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उत्पादों की कीमतों में भारी कटौती की है। कहीं जैकेट और स्वेटर आधी कीमत पर मिल रहे हैं, तो कहीं दो सामान खरीदने पर 60 फीसदी तक छूट दी जा रही है। सर्दियों के कपड़ों से लेकर फुटवियर और घरेलू उपयोग के उत्पादों तक पर छूट मिलने से मेले में खरीदारी बढ़ने लगी है। निजी दुकानों के साथ झारखंड सरकार के पवेलियन में भी विभिन्न उत्पादों पर 45 फीसदी तक छूट दी जा रही है। ऐसे में लोग मेले में सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि पसंदीदा सामान की खरीदारी करने भी पहुंच रहे हैं। मेले के हॉल में दुकानों के बाहर लगे छूट के बोर्ड ग्राहकों का ध्यान खींच रहे हैं। जैकेट, स्वेटर, हुडी और पुलोवर की दुकानों पर सर्दियों की खरीदारी करने वालों की भीड़ नजर आ रही है। वहीं फुटवियर और घरेलू उपयोग के उत्पादों की दुकानों पर भी ग्राहक पसंद के सामान तलाश रहे हैं। कई लोग एक दुकान पर सामान पसंद करने के बाद दूसरी दुकानों में उसकी कीमत पता कर रहे हैं।

इसके बाद दुकानदारों से मोलभाव कर कीमत कम कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। यानी मेले में खरीदारी के दौरान छूट के साथ मोलभाव का भी अलग रंग देखने को मिल रहा है। पालम निवासी सान्या मेले में स्वेटर और जैकेट खरीदने पहुंचीं। उन्होंने बताया कि यहां सर्दियों के कपड़ों पर करीब 50 से 60 फीसदी तक छूट मिल रही है। इतनी छूट मिलने से बजट में पसंद के कपड़े खरीदने का अच्छा मौका मिल रहा है। वहीं पालम से ही आई मानसी ने छूट का फायदा उठाते हुए फुटवियर खरीदे। उन्होंने बताया कि यहां पसंद के डिजाइन कम कीमत पर मिल गए। द्वारका निवासी मोहित ने हॉल नंबर एक और दो में खरीदारी की। उन्होंने बताया कि मेले में दुकानदारों से मोलभाव करने का भी मौका मिलता है। कई बार दुकानदार शुरुआती कीमत अधिक बताते हैं, लेकिन बातचीत करने पर कीमत कम कर देते हैं। उन्होंने भी मोलभाव के बाद सामान खरीदा। मेरठ से आई खुशी ने करीब 50 फीसदी छूट पर हुडी, मसाजर और क्रॉक्स खरीदे।

उमर खालिद और शरजील इमाम को अंतरिम जमानत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

नई दिल्ली (एजेंसी)



सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, दोनों की ओर से दायर जमानत याचिकाओं पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को खालिद और इमाम की नई जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अंतरिम जमानत पर जल्द विचार करने का आग्रह किया। सिब्बल ने कहा कि वह छह साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने अंतरिम जमानत की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत की मांग पर विचार करने से पहले वह दूसरे पक्ष (दिल्ली पुलिस) की बात सुनेगी। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि तीन जजों की बेंच गठित करने के लिए इस मामले को प्रशासनिक स्तर पर मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के समक्ष रखा जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, नोटिस जारी करें। रजिस्ट्री इस मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ के गठन के लिए प्रशासनिक स्तर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे। यह निर्देश इस साल 22 मई को 'तस्लीम अहमद' मामले में दो जजों की बेंच के एक आदेश के संदर्भ में दिया गया है। यह आदेश 'गुलफिशा फातिमा' मामले और 'केए नजीब' मामले के फैसलों के बीच संभावित विरोधाभास को देखते हुए दिया गया था।

'केए नजीब' मामले में कहा गया था कि लंबी हिरासत और मुकदमे में देरी जमानत का आधार बन सकती है, भले ही यूएपीए के तहत शर्तें कितनी भी सख्त क्यों न हों। सैयद इफ्तिखार अंद्राबी बनाम एनआईए' मामले में दो जजों की एक बेंच ने इस साल जनवरी के 'गुलफिशा फातिमा' फैसले के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाए। उस फैसले में दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था, जबकि पांच अन्य आरोपियों को राहत दे दी गई थी।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने तस्लीम अहमद और खालिद सैफी को छह महीने की अंतरिम जमानत देते हुए इस मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यूएपीए मामलों में जमानत से जुड़ी कानूनी स्थिति में दिख रहे विरोधाभासों को सुलझाया जा सके। गौरतलब है कि 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम छह साल से अधिक समय से जेल में हैं।

सम्पादकीय

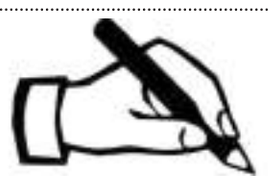

स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा

भारत के विकास की गति आज उसके मजबूत बुनियादी ढांचे से तय हो रही है। सड़कें, पुल, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे और औद्योगिक परियोजनाएं देश की आर्थिक प्रगति के प्रमुख आधार बन चुके हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन परियोजनाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक मशीनों के लिए भारत कब तक दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा? इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने घरेलू निर्माण उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला केवल औद्योगिक निवेश बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली कई आधुनिक मशीनें और उनके महत्वपूर्ण पुर्जे विदेशों से आयात किए जाते हैं। इससे न केवल विदेशी मुद्रा खर्च होती है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आने पर देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

सरकार की नई योजना का उद्देश्य भारतीय कंपनियों को घरेलू स्तर पर आधुनिक निर्माण उपकरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे देश में उत्पादन क्षमता विकसित होगी और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता घटाने का अवसर मिलेगा। इस योजना के तहत पात्र निर्माताओं को पांच वर्षों तक 8 से 13 प्रतिशत तक बिक्री आधारित प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इसके अलावा आधुनिक परीक्षण सुविधाओं के विकास के लिए 375 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इससे घरेलू कंपनियों को नई तकनीक अपनाने, उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने और वैश्विक बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप मशीनें विकसित करने में मदद मिल सकती है।

किसी भी देश की औद्योगिक मजबूती केवल बड़ी कंपनियों से नहीं, बल्कि छोटे उद्योगों और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला से भी बनती है। निर्माण उपकरण उद्योग के विस्तार से एमएसएमई क्षेत्र को नए अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही इंजीनियरिंग, मशीन निर्माण, अनुसंधान, तकनीकी प्रशिक्षण और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं। भारत के युवाओं को केवल मशीनों के उपयोग तक सीमित रखने के बजाय उनके निर्माण और तकनीकी विकास में भागीदार बनाना आवश्यक है।

हालांकि, इस योजना के सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं। भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनाना, अनुसंधान एवं विकास पर खर्च बढ़ाना और आधुनिक तकनीक का विकास करना आसान नहीं होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनाओं का लाभ केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे। छोटे और मध्यम उद्योगों को भी वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच मिलनी चाहिए। 11,000 करोड़ रुपये की यह योजना भारत के औद्योगिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। लेकिन किसी भी योजना की सफलता उसके बजट से नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले परिणामों से तय होती है।

जो पर्व हमारी स्मृति से मिट रहे हैं, उन्हें कौन बचाएगा?

सुरेश सिंह बैस शाश्वत

छत्तीसगढ़ की पहचान केवल उसकी भौगोलिक सीमा से नहीं होती। इसकी वास्तविक पहचान उसकी माटी, लोकभाषा, लोकगीत, लोककथाओं, लोकनृत्यों, लोककलाओं और पीढ़ियों से चली आ रही पर्व-परंपराओं में बसती है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में देश के दूसरे राज्यों की संस्कृति और पर्व-त्योहारों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अपनी धरती की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को उससे कहीं अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। प्रश्न यह नहीं है कि हम कितने पर्व मनाते हैं। असली प्रश्न यह है कि हम अपने कितने पारंपरिक पर्वों का मूल स्वरूप जानते हैं?

आज हरेली, तीजा, पोला, भोजली, गौरा-गौरी, कर्मा और छेरछेरा जैसे पर्व अपेक्षाकृत व्यापक पहचान रखते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा का संसार इससे कहीं अधिक विशाल है। जेठौनी, मातर, छेरता, धेरसा, मेघनाथ, आमाखाई, सुरहोती और दियारी जैसे अनेक पर्व और उनसे जुड़ी परंपराएं आज सीमित क्षेत्रों, विशेष समुदायों अथवा बुजुर्गों की स्मृतियों तक सिमटती जा रही हैं। उपलब्ध सांस्कृतिक स्रोतों में इन पर्वों का उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की लोक-संस्कृति केवल कुछ प्रसिद्ध पर्वों तक सीमित नहीं रही है।

मसलन, छेरछेरा पुन्नी केवल घर-घर जाकर धान मांगने का पर्व नहीं है। यह नई फसल, अन्नदान और सामाजिक समरसता से जुड़ी परंपरा है। पौष पूर्णिमा पर मनाए जाने वाले इस पर्व में बच्चे घर-घर जाकर अन्न मांगते थे और सामुदायिक जीवन में दान की भावना को जीवित रखते थे। इसी तरह भोजली केवल मिट्टी में अंकुर उगाकर विसर्जन करने की परंपरा नहीं है। इसमें कृषि, जल, प्रकृति, स्त्री-लोकजीवन और मित्रता इन सबका सुंदर समन्वय दिखाई देता है। भोजली में विभिन्न बीजों का अंकुरण और उसके बाद विसर्जन तथा 'मितान' बनाने की परंपरा छत्तीसगढ़ी लोकजीवन की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान रही है। गौरा-गौरी में शिव-पार्वती के विवाह की लोककल्पना है तो मातर में राउत/यादव समुदाय की विशिष्ट परंपरा दिखाई देती है। जनजातीय अंचलों में छेरता, धेरसा, आमाखाई और मेघनाथ जैसे पर्व भी कृषि, ऋतु, प्रकृति और सामुदायिक जीवन से जुड़े रहे हैं।

यही हमारी चिंता का विषय है। जब किसी पर्व का आयोजन केवल इसलिए बंद हो जाता है कि उसे मनाने वाली पीढ़ी कम होती जा रही है, तब उसके साथ केवल एक त्योहार समाप्त नहीं होता- उसके साथ एक लोकगीत, एक बोली, एक कथा, एक पारंपरिक व्यंजन, एक पूजा-पद्धति, एक सामाजिक संबंध और जीवन को देखने का एक पूरा लोकदर्शन भी धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए अब आवश्यकता केवल बड़े-बड़े सांस्कृतिक समारोह करने की नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक स्मृति का दस्तावेजीकरण करने की है। सरकार प्रत्येक जिले में ऐसे पर्वों की सूची तैयार कराए जो आज भी जीवित हैं, जो सीमित क्षेत्रों में मनाए जाते हैं और जो लगभग विस्मृति की ओर बढ़ चुके हैं। विश्वविद्यालयों, लोककला संस्थानों, साहित्यकारों, इतिहासकारों और स्थानीय बुजुर्गों की मदद से इनके इतिहास, लोकमान्यता, गीत, वाद्य, नृत्य, पूजा-विधि, पारंपरिक भोजन और सामाजिक महत्व का दस्तावेज तैयार किया जाना चाहिए। विद्यालयों में 'अपना लोकपर्व जानो' अभियान चल सकता है। प्रत्येक विद्यालय किसी एक स्थानीय पर्व को अपनाकर उसके बारे में बच्चों को जानकारी दे सकता है।

प्रेरणादायक विचार

कभी कभी व्यक्ति अपने आप को मजबुर समझकर ना चाहते हुए भी बड़ी ग़लती कर बैठता है अपने जीवन की और फिर वह अपनी ही गलती का पश्चात्ताप करता है खुद से और बार - बार गुस्सा करता है। फिर वह अपनी ग़लती को सुधारने का प्रयास करता है जिससे उसके काम में जो परेशानी आई है वह सही कर सकें।

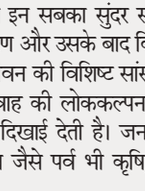

करिश्मा गुज्जर (खारी)

आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत

अक्षिता

किसी बच्चे के स्वस्थ बचपन और किसी गर्भवती महिला के सुरक्षित मातृत्व की शुरुआत केवल अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र से नहीं होती। इसके लिए पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच, सही जानकारी और समय पर मिलने वाली जरूरी सेवाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण भारत में इन जरूरतों को पूरा करने में आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है। खासकर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में, जहां गांव दूर-दूर तक बसे हैं और कई इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान नहीं है, वहां आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों और महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं की पहली कड़ी बनते हैं।

उत्तराखंड में वर्तमान में 20,067 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2026 में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सभी 20,067 आंगनबाड़ी केंद्रों में 'आंगन का मिलन' जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जानकारी भी दी गई थी। बागेश्वर जिले में ऐसे 834 केंद्र हैं। इतने बड़े नेटवर्क से यह समझा जा सकता है कि राज्य में बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य तथा पोषण को बेहतर बनाने में आंगनबाड़ी व्यवस्था कितनी अहम है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को केवल भोजन उपलब्ध कराने का काम नहीं होता। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत छह प्रमुख सेवाएं दी जाती हैं। इनमें पूरक पोषण, प्री-स्कूल गैर-औपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और जरूरत पड़ने पर रेफरल सेवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से उपलब्ध कराई जाती हैं। पोषण संबंधी मानकों को वर्ष 2023 में संशोधित किया गया है, जिसमें केवल कैलोरी पर नहीं बल्कि प्रोटीन, स्वस्थ वसा तथा आयरन, कैल्शियम, जिंक और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित संतुलित आहार पर जोर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार भी मातृ एवं बाल पोषण को लेकर अलग-अलग योजनाएं संचालित करती रही है। राज्य के बजट दस्तावेजों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पूरक पोषण कार्यक्रम जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इनके माध्यम से बच्चों और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। लेकिन किसी योजना की सफलता केवल इस बात से तय नहीं हो सकती कि उसके लिए कितने केंद्र बनाए गए या कितने लाभार्थियों का पंजीकरण हुआ।



असली सवाल यह है कि पहाड़ के आखिरी गांव तक उस योजना की सुविधा कितनी नियमितता और गुणवत्ता के साथ पहुंच रही है। बागेश्वर जिला मुख्यालय से लगभग 67 किलोमीटर दूर स्थित पिंगलो गांव का आंगनबाड़ी केंद्र इसी सवाल को सामने लाता है। पिंगलो में आंगनबाड़ी केंद्र का भवन अच्छा है। देखने में ऐसा लगता है कि बच्चों और महिलाओं के लिए एक व्यवस्थित जगह तैयार की गई है। लेकिन भवन का अच्छा होना और केंद्र की सभी सुविधाओं का उपलब्ध होना दो अलग-अलग बातें हैं।

यहां आने वाले बच्चों और महिलाओं को जरूरत के अनुसार हर सुविधा नियमित रूप से नहीं मिल पाती। कभी बच्चों को समय पर पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता तो कभी गर्भवती महिलाओं को मिलने वाला पूरा राशन उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे में एक अच्छी इमारत होने के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्र अपने पूरे उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाता। यह स्थिति केवल पिंगलो की समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं की जा सकती। पहाड़ी गांवों में भौगोलिक परिस्थितियां सेवा पहुंचाने की चुनौती को और बढ़ा देती हैं। सड़क, मौसम, दूरी, परिवहन और आपूर्ति व्यवस्था की कठिनाइयां मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक होती हैं। यदि किसी दूरस्थ केंद्र तक पोषण सामग्री समय पर नहीं पहुंचती, तो उसका सीधा असर उन बच्चों और महिलाओं पर पड़ता है जिनके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है।

इसलिए पहाड़ों में आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल एक भवन के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। वहां पर्याप्त पानी, स्वच्छ शौचालय, बच्चों के बैठने की व्यवस्था, खाना तैयार करने की सुविधा, आवश्यक पोषण सामग्री, खेल एवं सीखने की सामग्री और नियमित स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने की राष्ट्रीय पहल में एलईडी स्क्रीन, जल शुद्धिकरण व्यवस्था, पोषण वाटिका और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की सामग्री जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है। इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर भी केवल योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी डालना पर्याप्त नहीं है। वे गांव में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और परिवारों से सीधे जुड़ी होती हैं। इसलिए उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण, जरूरी सामग्री और समय पर मानदेय तथा प्रशासनिक सहयोग मिलना चाहिए। पोषण ट्रैकर जैसी डिजिटल व्यवस्था से लाभार्थियों और सेवाओं की निगरानी की जा रही है, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड तभी सार्थक होगा जब जमीन पर वास्तविक सेवा भी समय पर मिले। आंगनबाड़ी केंद्रों को गांव की जरूरतों के अनुसार अधिक उपयोगी बनाने के लिए समुदाय की भागीदारी भी बढ़ानी होगी। ग्राम पंचायत, आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अभिभावकों के बीच नियमित संवाद से यह पता लगाया जा सकता है कि किस केंद्र पर किस सुविधा की कमी है। महीने में होने वाले ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस जैसे आयोजनों को भी केवल औपचारिक गतिविधि न बनाकर महिलाओं और बच्चों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ना जरूरी है।

उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र सरकार और समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण पुल हैं। इस पुल को मजबूत करने के लिए केवल भवन बनाना पर्याप्त नहीं है। उसमें नियमित पोषण सामग्री, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षिक सामग्री और जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी उतनी ही जरूरी हैं। बच्चे के हिस्से का पौष्टिक भोजन समय पर पहुंचना और गर्भवती महिला को उसके लिए निर्धारित राशन नियमित रूप से मिलना कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का मूल उद्देश्य है।

इसलिए अब जरूरत इस बात की है कि उत्तराखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों की सफलता का आकलन केवल उनकी संख्या और भवनों से नहीं, बल्कि वहां पहुंचने वाले बच्चों और महिलाओं को वास्तव में मिल रही सेवाओं के आधार पर किया जाए। पहाड़ के दूर गांव में बना एक सुंदर आंगनबाड़ी भवन तभी सचमुच सफल माना जाएगा, जब उसके भीतर आने वाला हर बच्चा पोषण, देखभाल और सीखने का अधिकार पा सके और हर गर्भवती महिला को उसके हिस्से की जरूरी सहायता समय पर मिल सके।

म्यांमार: फ़ैसला अंत नहीं है

असद मिर्जा

अमेरिका की प्रतिक्रिया अधिक सतर्क रही। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने 2022 में औपचारिक रूप से माना था कि म्यांमार की सेना ने नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध किए, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वह आईसीजे के निर्णय का अध्ययन कर रहा है और न्यायालय के राजनीतिकरण से बचने के महत्व पर बल दिया। यह विरोधाभास एक केंद्रीय तनाव को उजागर करता है- रोहिंग्या के प्रति समर्थन इस राजनीतिक सावधानी के साथ भी रह सकता है कि अंतरराष्ट्रीय अदालतें नरसंहार को कैसे परिभाषित और लागू करती हैं। अतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का नवंबर 2026 का फ़ैसला एक ऐतिहासिक क़ानूनी हिसाब-किताब है- उसने म्यांमार को रोहिंग्या के विरुद्ध नरसंहार का ज़िम्मेदार ठहराया है। लेकिन केवल एक फ़ैसला नागरिकता बहाल नहीं कर सकता, सुरक्षित वापसी सुनिश्चित नहीं कर सकता और न ही व्यक्तियों को दंडित कर सकता है। इसका असर इस पर निर्भर है कि म्यांमार पालन करता है या नहीं, और सरकारें निंदा को निरंतर दबाव व व्यावहारिक संरक्षण में बदलती हैं या नहीं।

रोहिंग्या मुख्यतः मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक हैं, जिनकी जड़ें म्यांमार के राखाइन राज्य में गहरी हैं। उन्हें दशकों से भेदभाव और राज्य के दमन का सामना करना पड़ा है। 1982 के नागरिकता क़ानून ने व्यावहारिक रूप से अधिकांश रोहिंग्या को नागरिकता से वंचित कर दिया, उन्हें राज्यविहीन बना दिया और उनके आवागमन, शिक्षा तथा सेवाओं तक पहुंच को सीमित कर दिया। 'रोहिंग्या' नाम को नकारना उस व्यापक इनकार का हिस्सा बन गया कि यह समुदाय देश का हिस्सा है।

बहिष्कार से सामूहिक पलायन तक

संकट कई लहरों में गहराता गया, जिनमें 1978, 1991 और 2012 के सामूहिक विस्थापन शामिल हैं। 2016 में अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (अरसा) के सुरक्षा चौकियों पर हमलों के बाद सैन्य अभियान चले। 25 अगस्त 2017 को अरसा ने पुलिस और सैन्य ठिकानों पर हमला किया; सेना की प्रतिक्रिया कहीं अधिक विनाशकारी थी। बाद के हफ़्तों में सुरक्षा बलों ने गांव जलाए, नागरिकों की हत्या की और बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की। सात लाख से अधिक रोहिंग्या सीमा पार कर बांग्लादेश भाग गए।

यह पलायन कोई अलग-थलग घटना नहीं था। यह वर्षों के बहिष्कार का परिणाम था, और इसके बाद भी लाखों रोहिंग्या म्यांमार के भीतर कठोर पाबंदियों में रहते रहे। संयुक्त राष्ट्र के 2018 के तथ्य-अन्वेषण मिशन ने 2017 की हिंसा को व्यापक और सुनियोजित बताया और वरिष्ठ सैन्य नेताओं की जवाबदेही की माँग की। म्यांमार सरकार ने नरसंहार के आरोपों को ख़ारिज कर दिया और अपनी कार्रवाइयों को अरसा के विरुद्ध उग्रवाद-रोधी उपाय बताया।

मुक़दमा: कटघरे में राज्य, व्यक्ति नहीं

नवंबर 2019 में गांबिया ने, इस्लामी सहयोग संगठन के समर्थन से, म्यांमार के विरुद्ध आईसीजे में मामला दायर किया और 1948 के नरसंहार अभिसमय के उल्लंघन का आरोप लगाया। यह जनरलों के विरुद्ध आपराधिक मुक़दमा नहीं था। सवाल यह था कि क्या म्यांमार ने, एक राज्य के रूप में, नरसंहार को रोकने और दंडित करने के अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है।

जनवरी 2020 में न्यायालय ने म्यांमार को आदेश दिया कि वह रोहिंग्या की रक्षा और साक्ष्य सुरक्षित रखने के लिए अंतरिम उपाय करे। म्यांमार ने न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र और गांबिया के मामला लाने के अधिकार को चुनौती दी; जुलाई 2022 में न्यायाधीशों ने उसकी प्रारंभिक आपत्तियां ख़ारिज कर दीं, जिससे गुण-दोष पर कार्यवाही जारी रह सकी। जनवरी 2026 में सुनवाई हुई, जिसमें पीड़ितों की गवाही साक्ष्य का केंद्रीय हिस्सा थी।

19 नवंबर का फ़ैसला एक मील का पत्थर है- न्यायालय ने पाया कि म्यांमार ने 2017 के 'सफ़ाई अभियानों' के दौरान रोहिंग्या के विरुद्ध नरसंहार किया, और वह नरसंहार को रोकने तथा दंडित करने में विफल रहा। साथ ही म्यांमार ने साक्ष्य सुरक्षित रखने संबंधी 2020 के आदेश का उल्लंघन किया। फ़ैसले पर आई रिपोर्टों के अनुसार, न्यायाधीशों ने 9-6 के मत से माना कि सैन्य अभियान इस समूह को, कम से कम काफ़ी हद तक, नष्ट करने के इरादे से चलाया गया था। न्यायालय ने यह दावा ठुकरा दिया कि हिंसा के पैमाने और स्वरूप की व्याख्या केवल आतंकवाद-रोधी कार्रवाई से होती है।

न्यायालय का आदेश, और वह क्या नहीं कर सकता

न्यायालय ने म्यांमार को निर्देश दिया कि वह जारी उल्लंघन रोके, नरसंहार के उचित रूप से संदिग्ध लोगों की जांच करे और जहां उचित हो उन पर मुक़दमा चलाकर दंडित करे। उसने पुनरावृत्ति न होने के आश्वासन, रोहिंग्या के लिए पुनर्स्थापन, जिसमें सुरक्षित, स्वैच्छिक और गरिमामय वापसी तथा परिवारों के पुनर्मिलन की शर्तें शामिल हैं, और मुआवज़े का भी आदेश दिया। क्षतिपूर्ति की राशि और व्यवस्थाएं बाद के चरण में तय होंगी; म्यांमार को दो वर्ष के भीतर बहाली और मुआवज़े के उपायों पर रिपोर्ट देनी होगी।

ये आदेश बाध्यकारी हैं, किंतु आईसीजे के पास पुलिस बल नहीं है, न वह अधिकारियों को गिरफ़्तार कर सकता है और न म्यांमार के सैन्य नेतृत्व को सहयोग के लिए बाध्य। यदि कोई राज्य पालन न करे, तो दूसरा पक्ष मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जा सकता है, जो उपायों की सिफ़ारिश या निर्णय कर सकती है। यह मार्ग राजनीतिक रूप से अनिश्चित है- परिषद की शक्ति विवेकाधीन है और स्थायी सदस्य कार्रवाई रोक सकते हैं। इसलिए अनुपालन काफ़ी हद तक कूटनीतिक दबाव, अंतरराष्ट्रीय समन्वय और निरंतर निगरानी पर निर्भर करेगा।

प्रतिक्रियाएं: मान्यता, पर निश्चिंत होने की गुंजाइश नहीं

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने फ़ैसले का स्वागत किया और इसे पीड़ितों की मान्यता तथा इस बात की पुनर्पुष्टि बताया कि दंडमुक्ति हावी नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश से फ़ैसला देख रहे रोहिंग्या पीड़ितों के लिए यह सशक्त सार्वजनिक स्वीकृति थी। लेकिन रोहिंग्या पैरोकारों के अनुसार मान्यता पर्याप्त नहीं- पीड़ित चाहते हैं कि दुनिया उनकी बात सुने और उनके भविष्य से जुड़े निर्णयों में महिलाओं को शामिल करे।

अमेरिका की प्रतिक्रिया अधिक सतर्क रही। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने 2022 में औपचारिक रूप से माना था कि म्यांमार की सेना ने नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध किए, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वह आईसीजे के निर्णय का अध्ययन कर रहा है और न्यायालय के राजनीतिकरण से बचने के महत्व पर बल दिया। यह विरोधाभास एक केंद्रीय तनाव को उजागर करता है- रोहिंग्या के प्रति समर्थन इस राजनीतिक सावधानी के साथ भी रह सकता है कि अंतरराष्ट्रीय अदालतें नरसंहार को कैसे परिभाषित और लागू करती हैं। म्यांमार की सैन्य-समर्थित सरकार ने अब तक फ़ैसले पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह चुप्पी क़ानूनी निष्कर्ष को कमज़ोर नहीं करती, पर यह प्रश्न खुला छोड़ देती है कि क्या अधिकारी आदेश लागू करेंगे। यह फ़ैसला व्यक्तिगत अपराधियों की ज़िम्मेदारी भी तय नहीं करता; उसके लिए अलग आपराधिक कार्यवाही और राज्यों व संस्थाओं का सहयोग चाहिए।

लोकतंत्र का प्रहरी या सत्ता के सामने मौन होता मीडिया?

डॉ. प्रियंका सौरभ

लोकतंत्र की असली परीक्षा इस बात से नहीं होती कि सत्ता कितनी मजबूत है, बल्कि इस बात से होती है कि सत्ता से सवाल पूछने वाले कितने सुरक्षित हैं। जिस देश में पत्रकार सरकार की नीतियों, प्रशासनिक विफलताओं, भ्रष्टाचार और जनविरोधी फैसलों पर खुलकर सवाल पूछ सके, वहां लोकतंत्र जीवंत रहता है। लेकिन जिस व्यवस्था में सवाल पूछने वालों को ही संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगे, आलोचना को दुश्मनी समझा जाए और असहमति को अपराध की तरह प्रस्तुत किया जाए, वहां लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती पर चिंता स्वाभाविक है। प्रेस की स्वतंत्रता केवल पत्रकारों का अधिकार नहीं, बल्कि जनता का जानने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डु) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान इसी लोकतांत्रिक चेतना का आधार है। सर्वोच्च न्यायालय ने रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) और इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम भारत संघ (1985) जैसे मामलों में प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति के अधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। यह अधिकार सत्ता की कृपा से मिलने वाला उपहार नहीं, बल्कि लोकतंत्र में नागरिकों की संवैधानिक गरिमा का हिस्सा है। पत्रकारिता का दायित्व केवल घटनाओं का विवरण देना नहीं, बल्कि उन घटनाओं के पीछे छिपे सच को सामने लाना भी है। सरकारी योजनाओं की सफलता का प्रचार करना आसान है, लेकिन उन योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति, प्रशासनिक उदासीनता और जनता की पीड़ा उजागर करना साहस मांगता है। जब पत्रकार किसी घोटाले की पड़ताल करता है, किसी अधिकारी की जवाबदेही तय करता है, किसी पीड़ित की आवाज सत्ता तक पहुंचाता है या किसी नीतिगत निर्णय के परिणामों पर प्रश्न उठाता है, तब वह लोकतंत्र की रक्षा करता है। लेकिन यदि मीडिया सत्ता की उपलब्धियों का मंच बनकर रह जाए और उसकी विफलताओं पर मौन धारण कर ले, तो पत्रकारिता अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती है। लोकतंत्र में सत्ता को प्रश्नों से असुविधा हो सकती है, लेकिन प्रश्नों से असुविधा होना और प्रश्नों को दबाना दो अलग-अलग बातें हैं।

आज मीडिया के सामने सबसे बड़ा संकट केवल पत्रकारों की सुरक्षा का नहीं, बल्कि उनकी स्वतंत्रता और विश्वसनीयता का भी है। पत्रकारों पर दबाव अनेक रूपों में आता है। कभी विज्ञापन बंद करने की धमकी, कभी मुकदमों का भय, कभी सरकारी पहुंच से वंचित करना, कभी संस्थागत दबाव और कभी सीधे हिंसा के माध्यम से उनकी आवाज दबाने की कोशिश होती है। स्वतंत्र पत्रकारों के लिए यह संकट और गहरा है, क्योंकि उनके पीछे बड़े मीडिया संस्थानों की कानूनी टीम, आर्थिक संसाधन और संस्थागत सुरक्षा नहीं होती। एक फ्रीलांसर या स्थानीय पत्रकार किसी खबर की पड़ताल करते समय जितना जोखिम उठाता है, उसके बदले उसे अक्सर उतना आर्थिक और सामाजिक संरक्षण भी नहीं मिलता। पत्रकारिता का साहस पुरस्कारों और प्रशस्तियों से नहीं, बल्कि उस जोखिम से मापा जाता है जो सच सामने लाने के लिए उठाया जाता है।

पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा इस संकट का सबसे भयावह रूप है। गौरी लंकेश की 2017 में हत्या ने देश को झकझोर दिया था और यह प्रश्न छोड़ दिया था कि असहमति व्यक्त करने वाले पत्रकार आखिर कितने सुरक्षित हैं। किसी पत्रकार की हत्या केवल एक व्यक्ति की आवाज समाप्त नहीं करती, बल्कि समाज में भय का वातावरण पैदा करती है। जब एक पत्रकार पर हमला होता है, तो उसके साथ कई दूसरे पत्रकार भी अपनी खबरों, अपने शब्दों और अपने सवालों पर विचार करने लगते हैं। हिंसा का वास्तविक उद्देश्य केवल पीड़ित को चुप कराना नहीं, बल्कि उन सभी लोगों को भयभीत करना होता है जो सच लिखने का साहस रखते हैं। इस भय से पैदा होने वाली आत्म-सेंसरशिप किसी भी प्रत्यक्ष प्रतिबंध से अधिक खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसमें पत्रकार स्वयं अपनी कलम रोकने लगता है। डिजिटल युग ने पत्रकारिता को नई शक्ति दी है, लेकिन इसी डिजिटल दुनिया ने पत्रकारों के लिए उत्पीड़न का नया मैदान भी तैयार किया है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, धमकियां, चरित्रहनन, निजी जानकारी सार्वजनिक करना और संगठित ऑनलाइन हमले विशेषकर महिला पत्रकारों को निशाना बनाते हैं। किसी खबर से असहमति होना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन पत्रकार के परिवार, निजी जीवन और चरित्र पर हमला करना आलोचना नहीं, बल्कि उसे डराने की रणनीति है। जब किसी महिला पत्रकार को उसके विचारों के बजाय उसकी पहचान, व्यक्तिगत जीवन या लिंग के आधार पर अपमानित किया जाता है, तो यह केवल व्यक्तिगत उत्पीड़न नहीं, बल्कि सार्वजनिक संवाद को दूषित करने का प्रयास होता है। ऐसी परिस्थितियों में पत्रकारों का पीछे हटना केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं, समाज के सूचना अधिकार का नुकसान है।

डिजिटल निगरानी भी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। पत्रकारों के फोन, डिजिटल उपकरणों और संचार माध्यमों की निगरानी की आशंकाएं स्रोतों की गोपनीयता को खतरे में डालती हैं। खोजी पत्रकारिता में सूचना देने वाले व्यक्ति कई बार भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितताओं या संवेदनशील मामलों से जुड़े तथ्य सामने लाते हैं। यदि उन्हें यह भय हो कि उनकी पहचान उजागर हो सकती है, तो वे सामने आने से बचेंगे। परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण खबरें सार्वजनिक होने से पहले ही दम तोड़ सकती हैं। पेगासस से जुड़ा विवाद और 2021 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर गठित जांच व्यवस्था ने निगरानी, निजता और पत्रकारिता की स्वतंत्रता के प्रश्न को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। स्रोतों की सुरक्षा पत्रकारिता की तकनीकी आवश्यकता ही नहीं, लोकतांत्रिक विश्वास की बुनियादी शर्त है।

इंटरनेट बंद करना, डिजिटल सामग्री पर प्रतिबंध लगाना और सूचना के प्रवाह को बाधित करना भी पत्रकारिता की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट प्रतिबंधों की समीक्षा और आनुपातिकता के सिद्धांत पर बल दिया। डिजिटल माध्यम आज समाचार संकलन, प्रसारण, संवाद और जनसंपर्क का प्रमुख साधन है। इंटरनेट बाधित होने पर केवल नागरिकों की अभिव्यक्ति प्रभावित नहीं होती, बल्कि पत्रकारों की रिपोर्टिंग, समाचारों की पहुंच और सार्वजनिक विमर्श भी बाधित होते हैं। सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर प्रतिबंधों का औचित्य हो सकता है, लेकिन उनका अनिश्चितकालीन, व्यापक और अपारदर्शी उपयोग लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर कर सकता है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक विजय कुमार द्वारा ओ.एस. पब्लिकेशन, बी-2542, नरेला, इंडस्ट्रियल एरिया, नार्थ वेस्ट दिल्ली-110040 से मुद्रित कराकर 1536/108 गणेशपुरा रोड, त्रीनगर दिल्ली-110035 से प्रकाशित। सम्पादक : विजय कुमार RNI No. : DELHIN/2015/66886
अखबार में प्रकाशित तथ्यों एवं लेखों से सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं, किसी भी कानूनी वाद विवाद का निपटारा दिल

बात सीट की नहीं, जीत की है, अखिलेश यादव ने कांग्रेस से कहा, पीडीए प्रत्याशी बनाएं

लखनऊ (एजेंसी)



अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, हम चाहते हैं कि आप और हम जन-अपेक्षाओं व वास्तविकताओं को समझ कर गंभीर विचार-विमर्श करें, जिससे अधिकांश सीटों पर अपने गठबंधन की जीत सुनिश्चित हो। जितनी सीटें आप-हम लड़ें, उनमें हमारी जीत की सीटें, न जीत पाने वाली सीटों से अधिक हों

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस के साथ गठबंधन और उत्तर प्रदेश में सीट समायोजन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार एक ऐतिहासिक अवसर है, जब हम दोनों पंथनिरपेक्ष पार्टियां मिलकर सांप्रदायिक भाजपा और उनके संकीर्ण सोच के साथियों को हमेशा के लिए हराकर देश को गलत हाथों में जाकर बर्बाद होने से बचा सकते हैं।

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, 'हम चाहते हैं कि आप और हम जन-अपेक्षाओं व वास्तविकताओं को समझ कर गंभीर विचार-विमर्श करें, जिससे अधिकांश सीटों पर अपने गठबंधन की जीत सुनिश्चित हो। जितनी सीटें आप-हम लड़ें, उनमें हमारी जीत की सीटें, न जीत पाने वाली सीटों से अधिक हों। जीत ही बंटवारे को सम्मानजनक बनाएगी, क्योंकि जीती हुई सीट ही सम्मान दिलाएगी।' उन्होंने कहा, आपकी टीम की तरफ से प्राथमिकता के आधार पर दी गई सीटों में से जिन 26 सीटों पर आज बात हो गई है, उनके अतिरिक्त अन्य सभी संभावित सीटें चिह्नित करके हमें भेज दें। फिर मिल बैठकर देखेंगे कि कौन सी सीट और उस पर कौन सा कैंडिडेट जीतने की पोजिशन में है। हो सकता है कि हम अपने आंकलन और जीत के गणितीय समीकरण के आधार पर कांग्रेस को ऐसी कई जीतने वाली सीटों के बारे में भी बताएं, जिन पर उन्होंने किसी कारणवश विचार ही नहीं किया है। सपा प्रमुख ने कहा कि हमारी कोशिश तो ये है कि जब बड़े नेता बैठें तो सभी सीटों पर 'इंडिया' ब्लॉक के प्रत्याशी के रूप में बात हो, न कि कांग्रेस या सपा के प्रत्याशी के रूप में और सबसे अच्छी और सकारात्मक परिणाम देने वाली बात तो ये होगी कि हम लोग अपने प्रत्याशी को पीडीए प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करें। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा, जिस प्रकार लोकसभा में आपके संगठन ने पीडीए के साथ पूरी तरह सहयोग किया, वो सदैव सराहनीय रहेगा, क्योंकि उसने ही मिलकर सांप्रदायिक भाजपा को धूल चटाई थी। अब इस बार भी हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में और फिर केंद्र में भी भाजपा को हराएंगे।

जमीनी सर्वेक्षणों से ये बात साफ हो गई है कि हर शहर, मोहल्ले, गली व गांव तक ये बात पहुंच गई है कि जो पीड़ित है, वो पीडीए है। इसीलिए पूरे प्रदेश के हर समाज, हर वर्ग के पीड़ित, दुखी, अपमानित भाजपा के खिलाफ लामबंद हो गये हैं, क्योंकि उन सबको ये विश्वास है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा और पीडीए ही परिवर्तन लायेगा। उन्होंने कहा, सच तो ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि सीट का बंटवारा हमारे-तुम्हारे के भाव से हो, हम तो इसे बंटवारा नहीं, सीट समायोजन कहना चाहते हैं। कठिन समीकरण वाली सीटों पर हम मिलकर कम-से-कम दो प्रत्याशियों पर विचार-विमर्श करके जिसकी अधिक संभावना दिखेगी, उसे चुनकर मिलजुल के जिताएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि गठबंधन में एक-दूसरे पर उम्मीदवार थोपे जाएं, बल्कि सहमति से तय किए जाएं, तब ही आपके-हमारे वोट आपस में ट्रांसफर होकर हम लोगों की जीत को सुनिश्चित करेंगे और कल को हम मिलकर कह सकेंगे कि हम लोगों ने तो पहले ही कहा था, बात सीट की नहीं, जीत की है। उन्होंने कहा, आपका-हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य सरकार बनाना है। नये हालातों और समीकरण में उसके लिए हमें-आपको कुछ लोगों को एडजस्ट और एकमोडेट करना पड़ेगा। एक-दो लोग ऐसे भी होंगे, जिनसे आपने और हमने चुनाव लड़ने का वादा किया होगा, लेकिन वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए दो-चार सीटों पर बदलाव भी करने पड़ेंगे। भावी प्रत्याशियों को भी ये समझना होगा कि हर सीट महत्वपूर्ण है।

अगर किसी को सीट नहीं मिल पा रही है या मनचाही सीट नहीं मिल रही है तो निराश न हों, अगर उनके दल के बड़े नेता ने कुछ फेरबदल या बदलाव किया है तो उसके पीछे सोच सरकार बनाने की है और सरकार बन गई तो सबको सम्मान-स्थान मिल जाएगा। हर बड़ा नेता अपनी बात का मान खुद रखेगा, इतना विश्वास तो अपने नेताओं पर लोगों को रखना ही पड़ेगा।

यूपी चुनाव में सीटों पर उलझन के बीच सपा और कांग्रेस नेता बोले- भाजपा को सत्ता से हटाना है मकसद

लखनऊ (एजेंसी)



उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा और कांग्रेस में सीटों पर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। सपा की ओर से कांग्रेस को 26 सीटों की पेशकश और इसके बाद सपा द्वारा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी किए जाने के बाद कांग्रेस खेमे में खलबली मची हुई है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अलायंस मजबूत है और हमारा मकसद भाजपा को हराना है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर पहले दौर की बैठक में हमारे वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ इमरान मसूद और राजेंद्र पाल गौतम मौजूद थे।

बातचीत सकारात्मक रही है और इसमें प्रगति हुई है। हर सीट को लेकर अलग-अलग चर्चा हो रही है और अभी सभी निर्वाचन क्षेत्रों पर बात नहीं हो पाई है। एक बार जब चर्चा पूरी हो जाएगी, तो हम सारी जानकारी फाइनल कर लेंगे, इसके बाद साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी में हमारे किसी भी सहयोगी के साथ मेरा कोई मतभेद या असहमति नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य भाजपा को सत्ता से हटाना है। भाजपा देश को नुकसान पहुंचा रही है।समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और गठबंधन को मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों पार्टियां अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एकजुट हो रही हैं और उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर पूरी एकता और ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस नेता डॉ. रियाज ने कहा कि 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विचारधाराएं काफी मिलती-जुलती हैं और वे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे पर बातचीत कर रहे हैं।

कांग्रेस को 26 से ज्यादा सीटें देना ठीक नहीं, सपा कार्यकर्ता होंगे हताश : सांसद एसपी सिंह पटेल

लखनऊ (एजेंसी)



समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी सिंह पटेल ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही सीटों को लेकर फैसला हुआ है। राम गोपाल यादव ने कांग्रेस को 26 सीटों की लिस्ट दी है और यही फैसला सही है। एसपी सिंह ने कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत करीब 2 प्रतिशत था, जबकि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर करीब 32 प्रतिशत था। ऐसे में कांग्रेस को 26 से ज्यादा सीटें देना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हताश होंगे, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी-अपनी विधानसभाओं में मेहनत की है, उन्हें चुनाव लड़ने का हक मिलना चाहिए। इस समय जनाधार अखिलेश यादव के पक्ष में है और उन्होंने जो पीडीए का फॉर्मूला दिया है, उसमें सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों को सम्मान दिया जा रहा है।

जनता अखिलेश यादव के साथ है और यह बिल्कुल सही निर्णय है। सपा सांसद ने यह भी कहा कि अगले दौर की बातचीत भी होनी है, तो हो सकता है कि 2-4 सीटें और बढ़ जाएं। जो सीटें दी जा रही हैं, कांग्रेस को उन्हें मान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद के 'भीख' वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एसपी सिंह पटेल ने कहा कि इसमें भीख की क्या बात है, अपना वोट शेयर देखकर बात करिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस 30 से ज्यादा सीटों की हकदार नहीं है। यह आपसी सहयोग की बात है और देखना होगा कि वोट शेयर और जनता किसके पक्ष में है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल होने के नाते समाजवादी पार्टी का हक है कि हर निर्णय यहीं से लिया जाए। कांग्रेस को जितनी सीटें मिल रही हैं, उसे स्वीकार करनी चाहिए। उनके 2 प्रतिशत विधायक होने के बाद भी सबसे ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, यह उचित नहीं है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सीटें और दी जा सकती हैं। एसपी सिंह पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस बहुत पीछे है, जबकि समाजवादी पार्टी बहुत आगे है। आम आदमी पार्टी को भी 2-4 सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि वह भी गठबंधन में है।

'हम कोई भिखारी हैं, तय कर लें लड़ाई भाजपा से है या कांग्रेस से', सपा के प्रत्याशी उतारने पर इमरान मसूद का अखिलेश पर तंज

लखनऊ (एजेंसी)



कांग्रेस सांसद और यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने 'इंडिया' गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कोई भिखारी नहीं है और सीट बंटवारे की रणनीति पर स्पष्टता की मांग की है।

इमरान मसूद ने शायराना अंदाज में सपा पर तंज कसते हुए कहा कि 'उनको अच्छी नहीं लगती बुलंदी मेरी, उनको शायद मेरी परवाज बहुत खलती है।' उन्होंने कहा कि यह एक शेर है और यही जवाब है। सहारनपुर से दो प्रत्याशियों को उतारने के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा, 'कांग्रेस प्रत्याशी उतरना चाहती थी, क्यों कहा जा रहा है, जब कांग्रेस को उतारना होगा तो उतार देगी। इमरान मसूद ने कहा, 'गठबंधन के बीच में ऐसा काम किया जाएगा तो यह गठबंधन नहीं है। इसका मतलब यही है कि उनके अंदर गंभीरता नहीं है। अगर इस तरह से हो रहा है तो गठबंधन कहां है? अब हमारे नेतृत्व को तय करना चाहिए कि हमको क्या करना है? यह समझ से परे है कि इधर बात कुछ की जाती है और उधर हो कुछ जाता है। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, हमारे लिए यह बड़ा विषय नहीं है। मैं अपनी पार्टी से बंधा हूं। पार्टी जो कहेगी मुझे वही करना है। अखिलेश यादव की ओर से कांग्रेस के लिए 26 सीटें फाइनल करने के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा, हम कोई भिखारी थोड़ी ही हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस को भिखारी समझ रहे हैं। हमने उनसे सीटें मांगी नहीं और उन्होंने सीटें घोषित कर दीं। इसको गंभीरता नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस की आगे की रणनीति के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आ जाएं।

जो हमारा नेतृत्व कहेगा, हमको वही करना है। हमें उनकी (सपा) घोषणा से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन यह जरूर तय हो जाए कि लड़ाई भाजपा से है या कांग्रेस से है। सीट बंटवारे के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा, मेरा मानना है कि इस तरह से तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मुझे यही नहीं समझ आ रहा है कि हम लोग भिखारी थोड़ी हैं। हम उनसे (सपा) सीट मांग नहीं रहे हैं और उन्होंने हमारे लिए 26 सीटें घोषित कर दीं। हमारी ओर से तो कोई डिमांड भी नहीं की गई थी।

अगर इस तरह से 'तानाशाही' वाला रवैया अपनाया जाएगा तो मुझ जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति को ये बातें समझ नहीं आएंगी। इमरान मसूद ने कहा, मैं तो कांग्रेस से बंधा हूं और चर्चा के बाद कांग्रेस का आधिकारिक बयान सामने आएगा लेकिन सपा की ओर से जो किया जा रहा है, वह बेहतर नहीं है। जब उन्होंने (सपा) तय कर लिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इसमें रणनीति की बात ही नहीं है। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, मुझे अपनी पार्टी के लिए काम करना है। अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना है।

बिहार में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर : एक युवक की मौत, मेडिकल कॉलेज के दो छात्रों समेत चार घायल

मुजफ्फरपुर (एजेंसी)

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दो बाइकों की आमने-सामने की जोरदार टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक निजी मेडिकल कॉलेज के दो छात्र भी शामिल हैं। हादसा तुर्की थाना क्षेत्र के तुर्की-छाजन रोड पर रात के समय हुआ। घायलों में एक की हालत नाजुक देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है।

दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण जुट गए, जिससे कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार, तीन युवक तुर्की चौक स्थित मछली की दुकान से बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज के दो छात्र दूसरी बाइक से तुर्की की ओर जा रहे थे। तुर्की-छाजन रोड पर दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक पर सवार सभी पांच युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में छाजन मनरिया निवासी करीब 25 वर्षीय राकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, पंकज कुमार और महेश सहनी समेत चार अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। एक घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे पटना रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ वेस्ट-2 अनिमेष चंद्र ज्ञानी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि दो बाइकों की टक्कर में कुल पांच युवक घायल हुए थे। इनमें दो मेडिकल कॉलेज के छात्र और तीन स्थानीय ग्रामीण शामिल थे। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हैं। सभी घायलों की स्थिति गंभीर बताई गई है।

2027 तक बनेगा एआई और मशीन लर्निंग आधारित ग्लोबल डिलीवरी सेंटर, 200 युवाओं को मिलेगा रोजगार

पटना (एजेंसी)



बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की तैयारी है। राज्य में वर्ष 2027 तक एआई एवं मशीन लर्निंग आधारित ग्लोबल डिलीवरी सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके माध्यम से करीब 200 युवाओं के लिए उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस परियोजना को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में बिहार सरकार के सूचना प्रावैधिकी विभाग और एआई कंपनी टाइगर एनालिटिक्स इंडिया कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

पटना स्थित लोक सेवक आवास के 'संकल्प' सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इस समझौते पर सहमति बनी। परियोजना के तहत टाइगर एनालिटिक्स इंडस्ट्री पार्टनर की भूमिका निभाएगा। सरकार का उद्देश्य इस सेंटर के माध्यम से बिहार को देश के प्रमुख एआई इकोसिस्टम हब के रूप में विकसित करना है। इस ग्लोबल डिलीवरी सेंटर के माध्यम से राज्य के छात्र-छात्राओं, युवाओं, तकनीकी पेशेवरों और सरकारी अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे युवाओं की तकनीकी दक्षता और कौशल विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक, इस पहल से युवाओं को भविष्य की उभरती तकनीकों के अनुरूप रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर मिल सकेंगे।

इसके साथ ही राज्य में तकनीकी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बिहार सरकार राज्य में तकनीकी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए Bihar IT Policy 2024, Bihar GCC Policy 2026 और Bihar AI Policy 2026 लागू कर चुकी है। इन नीतियों के तहत कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन, आधुनिक तकनीकी आधारभूत संरचना और कारोबार स्थापित करने में सुगमता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सरकार का मानना है कि एआई और मशीन लर्निंग आधारित ग्लोबल डिलीवरी सेंटर की स्थापना से बिहार के आईटी और एआई इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी।

साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए राज्य में निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। इससे तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है। इस मौके पर सूचना प्रावैधिकी सह नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह और टाइगर एनालिटिक्स के वाइस प्रेसिडेंट एवं ग्लोबल हेड बद्रीश प्रकाश समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बिहार : आधी रात घर से बुलाकर युवक की गोली मारकर हत्या, 20 मीटर दूर ले जाकर माथे में मारी गोली

खगड़िया (एजेंसी)

बिहार के खगड़िया जिले में अपराधियों ने घर से बुलाकर 26 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात बुधवार देर रात गंगौर थाना क्षेत्र की वरैय पंचायत के दोघराहा गांव में हुई। अपराधियों ने युवक को घर से करीब 20 से 25 मीटर दूर ले जाकर माथे में गोली मार दी।

गोली आर-पार हो गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान वार्ड संख्या 14 निवासी सोनू कुमार उर्फ सोनू सदा (26) के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की मां ममता देवी ने बताया कि बुधवार रात करीब 1:30 बजे चार लड़के उनके घर पहुंचे थे। सभी सोनू को घर से बुलाकर बाहर ले गए।

इसके बाद घर से महज 20 से 25 मीटर की दूरी पर उसे गोली मार दी। गोली सोनू के माथे में लगी और आर-पार हो गई। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सोनू के पिता का नाम सोगारत सदा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव के लोग मौके पर जुट गए। परिवार में भी मातम पसर गया। वारदात की सूचना मिलने पर गंगौर थानाध्यक्ष श्याम सुंदर पासवान और सदर डीएसपी-2 संतोष कुमार पोद्दार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू की। साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। सदर डीएसपी-2 संतोष कुमार पोद्दार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अज्ञात अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की है। घटनास्थल पर एफएसएल टीम साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

भोजपुर में शादी समारोह के दौरान हथियारबंद बदमाशों ने की फायरिंग, दो युवकों की मौत



भोजपुर (एजेंसी)

बिहार के भोजपुर जिले में मंगलवार रात एक शादी समारोह के दौरान हथियारबंद अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इस फायरिंग में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। गोलीबारी की इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। यह मामला भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चकिया गांव का है। बताया गया कि चकिया गांव निवासी नरेश यादव की बेटी नेहा की शादी थी। बारात कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के पद्मिनिया गांव से आई थी। बारात आने के बाद जयमाला का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद सभी ने खाना खाया और आपस में बातचीत करने लगे। इसी दौरान दो बाइकों पर सवार छह हथियारबंद अपराधी वहां पहुंचे और बिना कुछ कहे फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी में किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। गोलियों की आवाज से पूरा समारोह दहल उठा।

देखते ही देखते शादी की खुशियां चीख-पुकार में बदल गईं। फायरिंग के दौरान एक युवक को बाएं कान और सिर के दाहिने हिस्से में गोली लगी, जबकि दूसरे युवक के पेट, दाहिने हाथ की बांह, बाएं हाथ के कंधे और कोहनी के पास गोली लगी। दोनों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शुभकरणगंज गांव निवासी सनोज यादव के 20 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार और महंत यादव के 21 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है। वहीं, जख्मी युवक दौलतपुर गांव निवासी सुरेंद्र यादव का 18 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार है। उसकी दाहिनी जांघ में गोली लगी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने राहुल और दीपक को मृत घोषित कर दिया। सोनू का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ वन सुशील कुमार पुलिस बल के साथ सदर अस्पताल पहुंचे। वहां जख्मी सोनू से घटना की जानकारी लेने के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू की।

ओपी राजभर का अखिलेश पर तंज, बोले- ओवैसी-चंद्रशेखर से घबरा गए, पहली सूची में उतार दिए चार मुस्लिम उम्मीदवार

लखनऊ (एजेंसी)



उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव घबराहट में हैं। ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन से अखिलेश यादव घबरा गए हैं। ओपी राजभर ने कहा, 'अखिलेश यादव को डर है कि मुस्लिम वोटर चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन की तरफ खिसक रहे हैं। इसी घबराहट में उन्होंने 5 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं।'

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गठबंधन की परवाह किए बिना अखिलेश यादव ने जो 5 सीटों की सूची जारी की है, उसमें एक तरफ वे चक्र और त्रिशूल लेकर अयोध्या में खड़े होते हैं और दूसरी तरफ 5 में से 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतार देते हैं। ओपी राजभर ने और तंज कसते हुए कहा कि यह तो वही बात हो गई कि 12 बजे सोकर उठते हैं तो अली-अली करते हैं और जब स्नान करके टीका लगा लेते हैं तो बजरंग बली करते हैं। पहले उन्हें अली याद आ रहे हैं, इसलिए 4 टिकट फाइनल हो गए। अतरौलिया सीट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी मुलाकात पर ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि उन्हें सीट बंटवारे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। सीट मांगना अलग बात है और सीट का मिलना अलग बात है, इसका फैसला दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर होता है। नितिन नवीन और अमित शाह ये फैसले लेते हैं।

बिहार : अख्तरूल ईमान के बयान पर महिला आयोग सख्त, सात दिन में मांगा जवाब

किशनगंज (एजेंसी)



विवाह समारोहों और महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष एवं अमौर विधायक अख्तरूल ईमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार राज्य महिला आयोग ने उनके बयान पर संज्ञान लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने विधायक से सात दिनों के भीतर लिखित जवाब मांगा है। निर्धारित समय में स्पष्टीकरण नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य सजल झा ने 24 नवंबर 2026 को यह नोटिस जारी किया। इसमें सार्वजनिक मंच से अमर्यादित, भड़काऊ और विवादास्पद बयान देने के मामले में विधायक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि उसके संज्ञान में अख्तरूल ईमान का एक वीडियो आया है। इसमें वह सार्वजनिक मंच से महिलाओं और विवाह समारोहों को लेकर कथित तौर पर अभद्र एवं अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं।

इसके साथ ही अन्य संवैधानिक मुद्दों पर भी भड़काऊ बयान देने का उल्लेख किया गया है। आयोग ने इस तरह की टिप्पणी को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला और सार्वजनिक मर्यादा के विरुद्ध बताया है। विधायक को नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल, अख्तरूल ईमान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें वह मुस्लिम समाज में विवाह के दौरान होने वाली रस्मों, दुल्हन की मुंह दिखाई, वलीमा में उपहार लेने और शादी में होने वाली फिजूलखर्ची को लेकर टिप्पणी करते नजर आए थे। इसी दौरान दुल्हन की नुमाइश की तुलना तवायफ से करने वाली उनकी टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया था। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके बयान की आलोचना की थी। अब बिहार राज्य महिला आयोग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद यह मामला नए सिरे से चर्चा में है। आयोग ने विधायक को अपना पक्ष रखने के लिए सात दिन का समय दिया है। फिलहाल अख्तरूल ईमान की ओर से नोटिस के जवाब में क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है, इस पर नजरें टिकी हैं।

आतंकवादी नई तकनीक का कर रहे इस्तेमाल, भारत ने दुनिया को किया हैकिंग के खतरे से आगाह

न्यूयॉर्क (एजेंसी)



पी. हरीश ने भारत ने कहा अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। पी हरीश बोले, भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और उभरती हुई तकनीकों के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। इससे पता चलता है कि भारत महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और जरूरी नागरिक सेवाओं के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दे रहा है

भारत ने दुनिया को आंतकियों के बदलते पैटर्न से आगाह किया है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत ने तकनीक के दुरुपयोग का हवाला देते हुए हैकिंग के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने मंगलवार (स्थानीय समयानुसार) को कहा कि आतंकवादियों और नॉन-स्टेट एक्टर्स द्वारा उभरती तकनीकों का संभावित दुरुपयोग बेहद गंभीर चिंता का विषय है।

'तेजी से होते तकनीकी बदलावों के दौर में संघर्ष समाधान' विषय पर सुरक्षा परिषद की एक चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के जरिए अधूरा, गलत या जानबूझकर बदला गया डेटा निर्णय लेने की प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। पी हरीश बोले, भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और उभरती हुई तकनीकों के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। इससे पता चलता है कि भारत महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और जरूरी नागरिक सेवाओं के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दे रहा है। उन्होंने आगे कहा, देश के भीतर, 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम' (आईटी एक्ट) और उससे जुड़े नियम अनधिकृत पहुंच, डेटा के साथ छेड़छाड़ और कंप्यूटर सिस्टम में बाधा डालने के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये नियम सशस्त्र संघर्ष के दौरान भी प्रासंगिक बने रहते हैं।

उन्होंने कहा, तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति, संघर्ष के स्वरूप और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य को पूरी तरह से बदल रही है। माइक्रोसॉफ्ट के एक अधिकारी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण डिजिटल बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरों की ओर ध्यान दिलाया। कंपनी के कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष फ्रेडरिक हम्फ्रीज ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट की '2026 डिजिटल डिफेंस रिपोर्ट' के अनुसार, साइबर हमलों का जवाब देने के लिए मिलने वाला समय कम होता जा रहा है। अब सॉफ्टवेयर या सिस्टम में पाई गई नई कमियों का फायदा उठाकर 24 घंटे से भी कम समय में एक सक्रिय हमला किया जा सकता है।

इस वजह से, संघर्ष को बढ़ने से रोकना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घटनाओं की पुष्टि करने या इरादों के बारे में बातचीत करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। हरीश ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वायत्त (ऑटोनॉमस) सिस्टम और उभरती हुई डिजिटल तकनीकें अभूतपूर्व अवसर तो लाती हैं, लेकिन साथ ही ये पूरे संघर्ष चक्र में नई कमजोरियां और जोखिम भी पैदा करती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिस्टम पर इंसानों का नियंत्रण सर्वोपरि होना चाहिए।

उन्होंने कहा, हथियार प्रणालियों के संचालन के संदर्भ और उनकी विशेषताओं को देखते हुए, इंसानों का निर्णय और निगरानी बहुत जरूरी है। ऐसे सिस्टम के इस्तेमाल की जिम्मेदारी हमेशा इंसानों की ही होनी चाहिए। हरीश ने इस बात पर चिंता जताई कि तकनीक के क्षेत्र में अंतर (टेक्नोलॉजी गैप) बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्यात नियंत्रण और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के कारण 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने इस प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना की, जिसमें 'ग्लोबल साउथ' के देशों को केवल 'उपभोक्ता' मान लिया जाता है, जबकि एआई जैसी उभरती तकनीकों के विकास, नियमन और तैनाती में उनकी कोई भूमिका या हिस्सेदारी नहीं होती। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, मूल रूप से, यह मुद्दा सत्ता का सवाल है -- कि एआई को कौन आकार देगा, कौन इसकी निगरानी करेगा और इससे किसे फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा, कई विकासशील देशों सहित अधिकांश देशों की उन एआई तकनीकों में बहुत कम भागीदारी रही है, जो उनके भविष्य को तय करेंगी।

रियाद पर ड्रोन हमले के बाद यमन की राजधानी में हवाई हमले

सना/रियाद (एजेंसी)



हूती समूह और सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच तनाव चरम पर है। मंगलवार देर रात यमन की राजधानी सना में बम बरसाए गए। हूती-संचालित अल-मसीराह टीवी ने बताया कि सना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के इलाके को सऊदी ने निशाना बनाया। हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है। स्थानीय निवासियों ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ को बताया कि इलाके में जोरदार धमाके हुए, जिससे आस-पास के घरों की खिड़कियां हिल गईं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी एक बयान में, हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने कहा कि पिछले 24 घंटों में सऊदी बलों ने पूरे यमन में 72 हवाई हमले और मिसाइल हमले किए हैं।

उन्होंने दावा किया कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ये हमले यमन के हूती समूह और सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन समर्थित सरकारी बलों के बीच बढ़ती शत्रुता के बीच हुए हैं। वहीं, हूती ने सऊदी अरब के अंदर गहराई तक स्थित ठिकानों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया है। इससे पहले मंगलवार को, सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि रियाद के फाइनेंशियल सेंटर की एक इमारत पर 'कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला' किया गया है। गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मलिकी ने 'एक्स' पर एक बयान पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि यह हमला एक ड्रोन के जरिए किया गया था। चेतावनी दी कि हूती समूह द्वारा 'जानबूझकर नागरिकों और नागरिक संपत्तियों को निशाना बनाने' का कड़ा जवाब दिया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर और अरब लीग ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने इसे सऊदी अरब की संप्रभुता का उल्लंघन और देश की सुरक्षा व स्थिरता के लिए खतरा बताया है।

अमेरिका में खसरे का कहर : दो की मौत, इस साल 5,838 मामले आए सामने

वाशिंगटन (एजेंसी)



अमेरिका में खसरे का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। दो राज्यों- विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में खसरे से जुड़ी दो और मौतें दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही दोनों राज्यों में इस साल इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या क्रमशः तीन और नौ हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों से टीकाकरण कराने की अपील की है। विस्कॉन्सिन के स्वास्थ्य सेवा विभाग ने मंगलवार को बताया कि लाफायेट काउंटी में एक वयस्क की खसरे से जुड़ी दिक्कतों के चलते मौत हुई है। परिवार की निजता का सम्मान करते हुए मृतक के बारे में अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं की गई। राज्य में इस साल अब तक खसरे के 920 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें शुक्रवार के बाद से सामने आए 88 नए मामले भी शामिल हैं। 918 मामले अगस्त में शुरू हुए प्रकोप से जुड़े हैं।

राज्य में इस साल 20 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। वहीं, पेंसिल्वेनिया के स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को सेंटर काउंटी के एक ऐसे निवासी की मौत की पुष्टि की, जो खसरे से संक्रमित पाया गया था और जिसका टीकाकरण नहीं हुआ था। विभाग ने मृतक की उम्र या पहचान से जुड़ी अन्य जानकारी नहीं दी। पेंसिल्वेनिया में इस साल अब तक 46 काउंटियों में खसरे के 1,638 मामले दर्ज किए गए हैं। 18 नवंबर के बाद से 49 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में संक्रमण के कारण 330 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इस साल खसरे से हुई नौ मौतें छह अलग-अलग काउंटियों में दर्ज की गई हैं। सेंटर काउंटी में यह पहली मौत है। पेंसिल्वेनिया में अप्रैल के अंत में संक्रमण फैलना शुरू होने के बाद से स्वास्थ्यकर्मियों ने 287 अस्थायी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से खसरा, मम्प्स और रूबेला (एमएमआर) के 7,400 से अधिक टीके लगाए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि संक्रमण पर काबू पाने के लिए और टीकाकरण केंद्र खोले जाएंगे। अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, 19 नवंबर तक देश में खसरे के 5,838 पुष्ट मामले दर्ज किए जा चुके थे।

'टर्की पार्डन' समारोह में ट्रंप का दावा, ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म

वाशिंगटन (एजेंसी)



ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध, तेल आपूर्ति, ईंधन की कीमतों और हालिया चुनावों पर भी अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया में पाले गए दो टर्की 'फ्रीडम' और 'फेदर्स' को परंपरा के अनुसार थैंक्सगिविंग के भोज में शामिल नहीं किया गया यानी उन्हें माफी दे दी गई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में थैंक्सगिविंग के पारंपरिक टर्की पार्डन समारोह के दौरान दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब न तो प्रभावी सेना बची है और न ही नौसेना। हालांकि, उसके पास कुछ मिसाइल दागने की क्षमता अभी भी है। मंगलवार को आयोजित इस समारोह में ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध, तेल आपूर्ति, ईंधन की कीमतों और हालिया चुनावों पर भी अपनी बात रखी।

इस दौरान उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया में पाले गए दो टर्की 'फ्रीडम' और 'फेदर्स' को परंपरा के अनुसार थैंक्सगिविंग के भोज में शामिल नहीं किया गया यानी उन्हें माफी दे दी गई। ट्रंप ने ईरान की सैन्य स्थिति का जिक्र करते हुए कहा, 'ईरान के पास कोई सेना नहीं है। उसके पास नौसेना भी नहीं है। उसकी सैन्य ताकत लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उसके पास मिसाइल दागने की थोड़ी क्षमता बची है।' उन्होंने दावा किया कि युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में अभी होर्मुज स्ट्रेट से अधिक तेल की आवाजाही हो रही है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी की भी तारीफ की और कहा कि अस्थायी रोक की अवधि को छोड़कर कोई ईरानी जहाज इस नाकेबंदी को पार नहीं कर पाया है। हालांकि, उन्होंने अपने दावों के समर्थन में तेल की आवाजाही के आंकड़े या ईरान की सैन्य स्थिति का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया।

होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवहन मार्गों में शामिल है। भारत सहित एशियाई देशों की तेल जरूरतों के लिहाज से इसका विशेष महत्व है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार, वर्ष 2024 में इस स्ट्रेट से भेजे गए कच्चे तेल और कंडेनसेट का 69 प्रतिशत हिस्सा चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को मिला था। हालांकि, ये ऐतिहासिक आंकड़े मौजूदा समय में तेल की आवाजाही की स्थिति की पुष्टि नहीं करते। समारोह के दौरान ट्रंप ने हालिया मध्यावधि चुनावों का भी जिक्र किया। वेस्ट वर्जीनिया में अपने मजबूत चुनावी प्रदर्शन को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे समझ नहीं आ रहा कि चुनाव में आखिर हुआ क्या। कोई मुझे समझाए।'

इस कार्यक्रम में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन भी मौजूद थे। ट्रंप ने उनके नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को लाना मुश्किल होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पेट्रोल की कीमतों में दो सप्ताह के भीतर 20 प्रतिशत गिरावट आने का भी दावा किया।

उन्होंने चुनाव के बाद कीमतों में आई गिरावट के समय को लेकर संदेह जताया। हालांकि, संघीय सरकार के साप्ताहिक आंकड़े इससे कम गिरावट दिखाते हैं। नियमित पेट्रोल की राष्ट्रीय औसत कीमत 9 नवंबर को 3.995 डॉलर प्रति गैलन थी, जो 23 नवंबर को घटकर 3.642 डॉलर प्रति गैलन रह गई। यानी इसमें करीब 8.8 प्रतिशत की कमी आई।

महाराष्ट्र : भिवंडी में चिकन शोरमा खाने से 43 लोग बीमार, गर्भवती महिला और 10 बच्चे अस्पताल में भर्ती

भिवंडी (एजेंसी)

महाराष्ट्र के भिवंडी में चिकन शोरमा खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया है। शोरमा खाने से अब तक 43 लोग बीमार हो गए हैं, जिनमें एक गर्भवती महिला और 10 बच्चे भी शामिल हैं। सभी मरीजों को इंदिरा गांधी स्मृति रुग्णालय (आईजीएम) में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

मरीजों के मुताबिक, अंजुर पट्टी नाके के पास स्थित एक दुकान से शोरमा खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को पेट में तेज दर्द, किसी को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, तो किसी को बुखार और चक्कर आने लगा। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य पेट दर्द समझा लेकिन जब एक साथ कई लोगों की तबीयत खराब हुई, तब पता चला कि फूड पॉइजनिंग है। पीड़ित शेख इरफान जाफर हुसैन ने बताया कि उन्होंने परसों रात अंजुर पट्टी नाके से शोरमा खाया था। उनका बच्चा शोरमा लेकर आया था, जिसे उन्होंने खा लिया। अगले दिन सुबह से ही उनके पेट में मरोड़ शुरू हो गई। दोपहर में न्यूज देखने के बाद उन्हें पता चला कि शोरमा खाने से ही लोगों की तबीयत खराब हो रही है। शाम तक उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया लेकिन आराम नहीं मिला। रात करीब 12 बजे उन्हें चक्कर और बुखार आ गया, जिसके बाद परिजन उन्हें आईजीएम अस्पताल लेकर आए। दूसरे मरीज ने बताया कि उन्होंने रात साढ़े नौ से साढ़े दस बजे के बीच शोरमा खाया था। अगले दिन दोपहर एक-डेढ़ बजे से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें बार-बार दस्त हो रहे हैं, पेट में ऐंठन हो रही है और उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। रात चार बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

उत्तरकाशी के पवाणी गांव में भीषण अग्निकांड : 33 मकान जलकर राख, 58 परिवार हुए बेघर

उत्तरकाशी (एजेंसी)



आग की लपटें इतनी तेज़ थीं कि गांव का पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय भी इसकी चपेट में आ गए। पुरोला के उपजिलाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस अग्निकांड में कुल 58 परिवार प्रभावित हुए हैं, जबकि गांव के केवल 13 मकान ही सुरक्षित बच पाए हैं

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की मोरी तहसील अंतर्गत दुर्गम पवाणी गांव में मंगलवार (24 नवंबर 2026) शाम लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गांव के 33 मकान जलकर पूरी तरह राख हो गए। आग की लपटें इतनी तेज़ थीं कि गांव का पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालय भी इसकी चपेट में आ गए।

पुरोला के उपजिलाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस अग्निकांड में कुल 58 परिवार प्रभावित हुए हैं, जबकि गांव के केवल 13 मकान ही सुरक्षित बच पाए हैं। राहत की बात यह है कि इस भयावह हादसे में अब तक किसी व्यक्ति के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। गैस सिलेंडर से आग लगने की आशंका; दुर्गम रास्ते के बावजूद मौके पर पहुंचीं बचाव टीमेंमवेशियों को भी पहुंचा नुकसानः उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण गैस सिलेंडर विस्फोट या रिसाव माना जा रहा है।

उन्होंने पुष्टि की कि हादसे में 33 आवासीय भवन प्रभावित हुए हैं और आग की चपेट में आने से ग्रामीणों के मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा है। पैदल मार्ग से गांव पहुंची रेस्क्यू टीमः जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, पवाणी गांव मोरी तहसील मुख्यालय से लगभग 55 से 60 किलोमीटर दूर स्थित है और मुख्य सड़क से करीब 300 से 400 मीटर पैदल चलकर ही गांव तक पहुंचा जा सकता है। सूचना मिलते ही पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल , अग्निशमन और राजस्व विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य संभाला।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख, प्रशासन को दिए त्वरित राहत के निर्देश

आवास, भोजन और चिकित्सा सुविधा की व्यवस्थाः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हृदयविदारक घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए सभी प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल अस्थायी आवास, भोजन, चिकित्सा सुविधा और अन्य आवश्यक राहत सामग्री की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

असम : बांग्लादेश सीमा के पास कुशियारा नदी से लापता बीएसएफ जवान का शव बरामद

गुवाहाटी (एजेंसी)

असम के श्रीभूमि जिले में बांग्लादेश सीमा के नजदीक कुशियारा नदी से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के लापता सैनिक के. बेनू का शव बरामद हुआ है। बेनू रविवार रात असम के कछार जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध मवेशी तस्करों के एक गिरोह का पीछा करते हुए बराक नदी में कूदने के बाद लापता हो गए थे। बीएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) ने जवान का शव मिलने की पुष्टि की।

साथ ही, उन्होंन पहले की उन खबरों को भी खारिज किया, जिनमें दावा किया गया था कि बेनू को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के जवानों ने जिंदा बचा लिया था और बांग्लादेश ले गए थे। डीआईजी ने साफ किया कि कांस्टेबल के जिंदा मिलने की खबरें गलत थीं। अधिकारियों के मुताबिक, बेनू और हेड कांस्टेबल जितेंद्र यादव कटिगोरा इलाके में हरिनगर बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात थे। उन्होंने चार से पांच संदिग्ध मवेशी तस्करों को बॉर्डर के पास घूमते देखा। बीएसएफ के जवानों को देखते ही संदिग्ध तस्कर गिरफ्तारी से बचने के लिए नदी में कूद गए। इसके बाद दोनों सुरक्षाकर्मी उनका पीछा करने के लिए नदी में उतरे। जितेंद्र यादव तैरकर सुरक्षित नदी के किनारे वापस आ गए लेकिन बेनू तेज बहाव में फंस गए और बह गए। सोमवार सुबह बीएसएफ कंपनी कमांडर ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लापता कांस्टेबल का पता लगाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), रिवर पुलिस और दूसरी एजेंसियों के कर्मियों को लगाया गया। सर्च टीमें सोमवार से ही नदी के किनारे ऑपरेशन कर रही थीं।

कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से केरल सीएम ने बनाई दूरी, सोशल मीडिया की खबरों को बताया फर्जी

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)



केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बुधवार को कांग्रेस के अंदर चल रही जुबानी जंग से खुद को दूर रखते हुए कहा कि पार्टी का संगठनात्मक नेतृत्व ही इन मुद्दों को संभालेगा। उन्होंने विभिन्न मीडिया संगठनों के नाम पर फैलाई जा रही कई खबरों को मनगढ़ंत बताया। साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम सतीशन ने कहा, मैं पार्टी के मामलों पर नहीं बोलूंगा। केपीसीसी अध्यक्ष और संगठनात्मक टीम जो जरूरी होगा, वह करेगी। मैं इसमें पक्षकार नहीं हूं। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी खुलकर सामने आने के बीच उनकी यह टिप्पणी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि वरिष्ठ नेता लगातार तीखे बयान दे रहे हैं, जिससे अंदरूनी मतभेद सार्वजनिक तमाशा बनने का खतरा पैदा हो गया है। पार्टी और सरकार के खिलाफ खबरों, खासकर सोशल मीडिया पर, के बारे में सीएम सतीशन ने कहा कि वे फर्जी हैं और उन्हें पता है कि ये कहां से आ रही हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया पर आ रही हर ऐसी खबर पर जवाब देने की जरूरत है। शुरू में मैं थोड़ा चिंतित था, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है। ऐसी खबरें डालने वालों की ही विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। मैं उन पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा।

सरकारी एलपी स्कूल टीचर (एलपीएसटी) रैंक लिस्ट के उम्मीदवारों के चल रहे आंदोलन पर मुख्यमंत्री ने माना कि सरकार मुश्किल स्थिति में फंस गई है। नियुक्ति अनुपात में बदलाव की मांग, सेवारत शिक्षकों को बचाने की सरकार की जिम्मेदारी से टकरा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी लोअर प्राइमरी स्कूलों में 3.49 लाख छात्र हैं, जबकि निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात 1:30 है। लेकिन मौजूदा अनुपात करीब 1:19 है, कुछ जिलों में यह 1:11 तक कम है और मलप्पुरम में सबसे ज्यादा 1:25 है। सीएम सतीशन ने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारी उम्मीदवारों की पांच में से चार मांगें मान ली हैं, लेकिन अनुपात वाली मांग अभी भी विवादास्पद बनी हुई है। उन्होंने लोक सेवा आयोग पर भी आरोप लगाया कि उसने जमीनी हकीकत का ठीक से आकलन किए बिना सिफारिशें कीं। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार की जिम्मेदारी मौजूदा स्टाफ को बचाने की है। जब छात्रों की संख्या घट रही है, तो हम पहले से सेवा में मौजूद शिक्षकों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सरकार की अपनी सीमाएं हैं, और हम इस स्थिति में फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि नई लिस्ट उपलब्ध होने के बावजूद सरकार ने रैंक लिस्ट की वैधता छह महीने बढ़ा दी थी।

बाबा महाकाल का गणेश स्वरूप में हुआ शृंगार, भस्म आरती में उमड़े श्रद्धालु, पीएम मोदी के भाई ने किए दर्शन

उज्जैन (एजेंसी)



विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में मार्गशीष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि बुधवार की सुबह 4 बजे हुई भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का पंचामृत पूजन-अभिषेक कर आकर्षक शृंगार किया गया। शृंगार के बाद बाबा महाकाल को भस्म रमाई गई। इस दौरान भक्तों ने इन दिव्य दर्शनों का लाभ लिया और जय श्री महाकाल के उद्घोष से मंदिर परिसर गूंज उठा। मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि मार्गशीष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि बुधवार पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का विशेष शृंगार किया गया।

इस दौरान भस्म आरती के लिए सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही पण्डे पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर फलों के रस से बने पंचामृत को अर्पित कर किया। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंड माला धारण करवाई गई। बुधवार के शृंगार की विशेष बात यह रही कि बाबा महाकाल का भांग से श्री गणेश के रूप में शृंगार किया गया। फिर बाबा महाकाल ने दिव्य दर्शन दिए। बाबा महाकाल की भस्म आरती में बड़ी संख्या मे श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने बाबा महाकाल के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और बाबा महाकाल की भक्ति में लीन होकर जय श्री महाकाल का उद्घोष करने लगे।

'पंजाब में भाईचारे का गठबंधन, बनेगी एनडीए सरकार': एचएस फूलका

पंजाब (एजेंसी)



भाजपा नेता और वरिष्ठ वकील एचएस फूलका ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा-शिरोमणि अकाली दल के साथ आने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह भाईचारे का गठबंधन है और प्रदेश में अगली सरकार एनडीए की बनेगी। नई दिल्ली में फूलका ने भाजपा-शिअद के गठबंधन के अलावा आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। गठबंधन पर फूलका ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकाली-भाजपा गठबंधन की घोषणा के लिए गुरु नानक देवजी के गुरुपुरब का दिन चुना और इसका बहुत बड़ा महत्व है। यह गुरु नानक देव के सिद्धांतों का पालन करने और मानवता को सबसे ऊपर रखने के बारे में है। यह कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं है बल्कि यह भाईचारे का गठबंधन है। यह हिंदू-सिख भाईचारे की मजबूती का एक सशक्त संदेश देता है और बताता है कि कोई भी इन दोनों समुदायों के बीच दरार नहीं डाल सकता। शुरुआत से ही दोनों दलों खासकर भाजपा ने हमेशा यही कहा है कि अकाली दल के साथ हमारा गठबंधन कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं बल्कि भाईचारे का गठबंधन है। इसे चुनावों के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, यह एक भावनात्मक फैसला है। पंजाब भारत का एकमात्र सिख-बहुसंख्यक राज्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि उन्होंने पंजाब में जो समय बिताया, वह उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दौर में से एक था। उन्हें पंजाब पसंद है और सिख समुदाय के प्रति उनके मन में बहुत स्नेह है। पंजाब के लोग, खासकर सिख चाहते थे कि दोनों दल एकजुट हो, इनका एकजुट होना ही सही है। पंजाब के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी एकजुट होना सही है। सिख समुदाय इस गठबंधन से खुश है। पंजाब में चुनाव जीतने के बाद एनडीए की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी के बारे में फूलका ने कहा कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी अपने रास्ते से भटक गई। मुझे 2015 में ही एहसास हो गया था कि पार्टी अपने सिद्धांतों से दूर हो गई है। अगस्त 2015 में मैंने आम आदमी पार्टी में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, जनता के दबाव के कारण, मैंने उस समय पार्टी नहीं छोड़ी। इसके बाद, मैंने देखा कि पार्टी की हालत और खराब होती गई और उसका कामकाज भी बिगड़ता गया। जब सज्जन कुमार मामले में अंतिम सुनवाई आई, तो मैंने पार्टी भी छोड़ दी।

एक फोन कॉल और फिर 28 छक्कों की बरसात! : युवराज सिंह सलाह ने वैभव सूर्यवंशी को बेखौफ बनाया?

दोहा (एजेंसी)



वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ महज 53 गेंदों में 204 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया था। उनकी इस तूफानी पारी के पीछे एक खास शख्स की सलाह और 30 मिनट की फोन पर हुई बातचीत का भी अहम योगदान रहा।

अब बीसीसीआई ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वैभव ने अपनी ऐतिहासिक पारी के पीछे की कहानी बताई और उस बातचीत का खुलासा किया। बीसीसीआई ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- युवराज सिंह के साथ 30 मिनट की फोन पर हुई बातचीत ने वैभव सूर्यवंशी की झिझक दूर कर दी। इसके बाद उन्होंने 28 छक्के और सात चौके की मदद से 204 रन की विश्व रिकॉर्ड पारी खेलकर इतिहास रच दिया।

इस युवा सनसनी ने अब अपनी अविश्वसनीय पारी के पीछे की कहानी बताई है और खुलासा किया है कि आखिर वह ऐतिहासिक पल कैसे आया। वीडियो की शुरुआत में वैभव कहते हैं, 'चलो बैठ जाते हैं, पांव दुख रहा है।' फिर दर्शक दीर्घा से कुछ फैंस चिल्लाते हुए नजर आते हैं, 'एक...दो...तीन...चार, वैभव भैया छक्के मार।' इसके बाद उनसे कहा जाता है कि उन्होंने सबसे तेज 150 और सबसे तेज 200 का रिकॉर्ड बना दिया है। इस पर वैभव ने कहा, 'सबसे तेज 150? वो तो मेरा ही रिकॉर्ड था। मैंने फिर इसे तोड़ दिया।' आगे वैभव बताते हैं, 'मैंने कल (मैच से एक दिन पहले) चार लोगों से बात की। सिर्फ चार लोगों से। एक तो मेरे पिता। एक मेरे बचपन के कोच मनीष ओझा। एक मेरे अंडर-19 क्रिकेट का एक दोस्त प्रथम जाचक।

चौथे युवराज सिंह सर थे। उनसे मैंने करीब आधे घंटे बात की। उन्होंने मुझे काफी कुछ समझाया और बताया बैटिंग को लेकर। इस मैच से पहले मैंने उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेला था, तो मैं काफी परेशान था। इस वजह से मैंने युवराज सर से खुल कर बात की। मैंने उन्हें बताया कि जब भी मैं बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर जाता हूं, मुझे ये-ये समस्याएं आ रही हैं। तो उन्होंने मुझे अच्छे से सबकुछ आधे घंटे तक एक्सप्लेन किया।' वैभव ने बताया, 'युवराज सर ने मुझसे बस इतना कहा कि अगर तुम 20 बॉल खेलते हो तो स्कोर अलग होगा। और भी कई टेक्निकल चीजें उन्होंने मुझे बताईं। इसने मुझे 204 रन बनाने में काफी मदद किया। माइंडसेट बस ये था कि जाकर देखूं विकेट कैसा है। यही किया मैंने। विकेट पर जाकर एक दो गेंद देखा।

वैभव ने किन तीन मैचों का किया जिक्र?

वैभव पिछले कुछ मैचों में रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। इस मैच से पहले पिछली सात पारियों में उनके बल्ले से कुल 157 रन निकले थे। इनमें 11, 26, 18, 45, 4, 15 और 38 रन की पारियां शामिल हैं। 11 रन उन्होंने पाकिस्तान-ए के खिलाफ पिछले मैच में बनाए थे। वहीं, 26 रन वैभव ने नेपाल के खिलाफ बनाए थे। 18 रन उन्होंने बिहार के लिए खेलते हुए सौराष्ट्र के खिलाफ बनाए थे।

भारत के न्यूजीलैंड दौरे पर दो टी20 में उन्हें खेलने का मौका मिला था, जिसमें उन्होंने 45 और चार रन की पारियां खेली थीं। वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ एशियन गेम्स फाइनल में वैभव ने 15 रन और श्रीलंका के खिलाफ एशियन गेम्स में ही 38 रन बनाए थे।

वैभव का अब तक क्रिकेटिंग करियर

वैभव ने अब तक 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेले हैं। इसमें 29.50 की औसत और 185.53 के स्ट्राइक रेट से 295 रन बनाए हैं। इनमें दो अर्धशतक शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 11 फर्स्ट क्लास और 16 लिस्ट-ए मैच भी खेले हैं। 11 फर्स्ट क्लास मैचों में उनके नाम 23.47 की औसत और 96.61 के स्ट्राइक रेट से 399 रन हैं। इनमें दो अर्धशतक शामिल हैं।

इसके अलावा 16 लिस्ट-ए मैचों में वैभव ने 50.31 की औसत और 193.04 के स्ट्राइक रेट से 805 रन बनाए हैं। इनमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। ओवरऑल 45 टी20 में वैभव ने 40.68 की औसत और 212.84 के स्ट्राइक रेट से 1790 रन बनाए हैं। इनमें चार शतक और आठ अर्धशतक भी शामिल हैं।

'युवराज सर मेरे आदर्श हैं, उनकी सलाह काम आई'



वैभव ने कहा, 'यह आसान नहीं था। मैंने आपको बताया न कि पिछले दो मैच जैसे गुजरे, और उससे पहले भी एक डोमेस्टिक मैच मैंने खेला था, तो रन नहीं बने थे। तो थोड़ा मेरा मन डायवर्ट हो रहा था कि क्या चल रहा है। फिर युवी सर से मैंने बात की और युवी सर मेरे आदर्श हैं और जब आप अपने आदर्श से बात करते हो तो उनकी हर बात ध्यान से सुनते हो। तो मैंने युवी सर की बात ध्यान से सुनी और उन्होंने काफी सारी चीजें पॉइंट पॉइंट की बताई। फिर मैंने भी अपनी बैटिंग के वीडियोज देखे तो लगा कि यहां पर मैं ये गलती कर रहा हूं। तो मैंने यूएई के खिलाफ कोशिश किया कि वो गलती न करूं। युवी सर ने जो मुझे एक-दो चीजें बताई, वो इस्तेमाल करूं। उसने मेरी काफी मदद की।'

वैभव सूर्यवंशी ने किसे बनाया अपना फैन?: विश्वकप विजेता कप्तान ने कही दिल की बात, बोले- अब आप मेरी प्रेरणा हो

भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने मंगलवार को दोहा में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। उन्होंने एसीसी राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 में यूएई के खिलाफ भारत ए की ओर से खेलते हुए महज 53 गेंदों में 204 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। उनकी इस पारी के बाद भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी उनके मुरीद हो गए। सूर्या ने वैभव की तारीफ करते हुए उन्हें अपनी प्रेरणा तक बता दिया। उनके अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ और एस बद्रीनाथ ने भी युवा बल्लेबाज की जमकर सराहना की।

टी20 विश्व कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वैभव की तारीफ करते हुए लिखा, 'वैभव सूर्यवंशी, अब तुम मेरी प्रेरणा हो। क्या खिलाड़ी है। खास।' सूर्यकुमार के इस संदेश ने युवा बल्लेबाज की ऐतिहासिक पारी के प्रभाव को दिखाया। वैभव ने अपनी बल्लेबाजी से लिस्ट-ए क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। वैभव ने यूएई के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उन्होंने महज 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इसके साथ ही वह लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर-मैकगर्क का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2023 में 29 गेंदों में शतक लगाया था। इसके बाद वैभव ने 40 गेंदों में 150 रन पूरे कर लिए। उन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड बेहतर किया। इससे पहले उन्होंने बिहार की ओर से अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 59 गेंदों में 150 रन बनाए थे। वैभव ने महज 52 गेंदों में दोहरा शतक पूरा कर लिया।

इससे पहले लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के चैड बोवेस के नाम था, जिन्होंने 103 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी। वैभव ने अपनी पारी में सात चौके और 28 छक्के लगाए। लिस्ट-ए क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अब उनके नाम हो गया है। उन्होंने डर्सी शॉर्ट का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2018 में 23 छक्के लगाए थे। वैभव 204 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वह रिकॉर्ड बुक में अपना नाम कई बार दर्ज करा चुके थे।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने वैभव की प्रतिभा की तारीफ करते हुए लिखा, 'असाधारण प्रतिभा! इतनी कम उम्र में दोहरा शतक वैभव सूर्यवंशी की निडर मानसिकता और असाधारण क्षमता को दर्शाता है।

महाकाल के दरबार में पहुंचे चहल-नीतीश और राहुल: भस्म आरती में हुए शामिल, मंदिर की किस व्यवस्था से हुए प्रभावित?



नई दिल्ली (एजेंसी)

भारतीय क्रिकेटर नीतीश राणा, युजवेंद्र चहल और राहुल तेवतिया बुधवार की सुबह उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर पहुंचे। तीनों क्रिकेटरों ने भस्म आरती में शामिल हुए और भगवान महाकाल के दर्शन करने के साथ ही पूजा-अर्चना की। सभी खिलाड़ी प्रातःकालीन दिव्य भस्म आरती में शामिल हुए और नंदी हॉल में बैठकर भगवान की आराधना की।

दर्शन के बाद खिलाड़ियों ने मंदिर समिति द्वारा की गई सुगम और वीआईपी दर्शन व्यवस्था की प्रशंसा की। स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल ने कहा, 'जब भी भस्म आरती देखने आते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। मंदिर द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं, उनसे कभी भी पूजा-पाठ या दर्शन में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। बहुत ही आराम से दर्शन होता है। भक्तों की कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, यहां कोई दिक्कत नहीं होती।' नीतीश राणा ने कहा, 'मैं यहां पर भस्म आरती के लिए आया था। मैं पहले भी कई बार यहां आ चुका हूं। मैं जिंदगी में कभी भी परेशान होता हूं या दुविधा में होता हूं, तो महाकालेश्वर आता हूं। भगवान महाकाल के दर्शन करता हूं। मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी है।' युजवेंद्र चहल और नीतीश राणा दोनों भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, जबकि राहुल तेवतिया को टीम इंडिया की तरफ से डेब्यू का मौका नहीं मिला है। हालांकि, तीनों खिलाड़ियों को देखने का मौका फैंस को आईपीएल में मिलता है।

सुपर 90 : 3 दिसंबर से शुरू होगा चौथा सीजन, गेल, हेल्स, रॉय, हसन जैसे स्टार खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

नैरोबी (एजेंसी)



पूर्व इंटरनेशनल स्टार क्रिस गेल, शाकिब अल हसन, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, तिलकरत्ने दिलशान, शॉन मार्श, फैबियन एलन और कार्लोस ब्रैथवेट 3 दिसंबर को केन्या के नैरोबी में शुरू होने वाले सुपर 90 सीजन 4 में मुख्य आकर्षण होंगे। टूर्नामेंट के चौथे एडिशन में कई जाने-माने इंटरनेशनल क्रिकेटरों वाली सात फ्रेंचाइजी एक साथ आएंगी, जिससे 12 दिनों तक रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। इस कॉम्पिटिशन में 22 मैच होंगे। फाइनल 14 दिसंबर को होगा।

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल पंजाब टाइटन्स के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे, जबकि बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन लंदन जायंट्स के लिए खेलेंगे। इंग्लैंड के जेसन रॉय और एलेक्स हेल्स क्रमशः मेरू थंडर्स और नैरोबी लायंस की तरफ से खेलेंगे। श्रीलंका के पूर्व कप्तान तिलकरत्ने दिलशान भी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर शॉन मार्श के साथ टूर्नामेंट में अपना अनुभव लेकर आएंगे। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर फैबियन एलन और कार्लोस ब्रैथवेट इंटरनेशनल लाइनअप को और मजबूत करेंगे। टूर्नामेंट में कई और जाने-माने इंटरनेशनल नाम भी होंगे, जिनमें एविन लुईस, क्रिस लिन, इमाद वसीम, महमूदुल्लाह, वेन पार्नेल, रवि बोपारा, अंबाती रायुडू, मिशेल जॉनसन और समित पटेल शामिल हैं, जो हिस्सा लेने वाली टीमों में और गहराई और अनुभव जोड़ेंगे।

शुरुआती मैच में पंजाब टाइटन्स का मुकाबला 3 दिसंबर को नैरोबी जिमखाना क्रिकेट क्लब में दिल्ली रॉयल्स से होगा। नैरोबी लायंस का मुकाबला 4 दिसंबर को लंदन जायंट्स से होगा, जबकि दिल्ली रॉयल्स उसी दिन बाद में हरियाणा वॉरियर्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी।

लंदन जायंट्स का मुकाबला 5 दिसंबर को एल्डोरेट टाइगर्स से होगा, जबकि मेरू थंडर्स उसी दिन पंजाब टाइटन्स के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करेगी। सात फ्रेंचाइजी–हरियाणा वॉरियर्स, पंजाब टाइटन्स, नैरोबी लायंस, मेरू थंडर्स, एल्डोरेट टाइगर्स, दिल्ली रॉयल्स और लंदन जायंट्स–के साथ, यह टूर्नामेंट इंटरनेशनल और केन्याई क्रिकेटरों को एक साथ लाएगा, जिससे खिलाड़ियों को एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म मिलेगा और देश में क्रिकेट को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैच रोजाना दो स्लॉट में खेले जाएंगे। भारतीय समयानुसार पहला मैच दोपहर 2 बजे से और दूसरा शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा।

दो बार पिछड़ने के बावजूद, मैन सिटी ने नेपोली के खिलाफ हार से बचने में कामयाबी हासिल की

मैनचेस्टर (एजेंसी) मैनचेस्टर सिटी को एतिहाद स्टेडियम में यूईएफए चैंपियंस लीग के मुकाबले में नेपोली के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेलना पड़ा। रेयान चेर्की के 86वें मिनट में किए गए गोल से सिटी घर में हार से बच सकी। सिटी इस मैच में दो बार पिछड़ी, लेकिन दोनों बार वापसी करते हुए एक अंक हासिल किया। इस ड्रॉ से सिटी की हालिया खराब फॉर्म को लेकर चिंता कम नहीं हुई है। टीम ने सभी प्रतियोगिताओं में अपने पिछले सात मैचों में सिर्फ एक जीत हासिल की है। मेजबान टीम ने अटैकिंग अंदाज में शुरुआत की। इलियट एंडरसन ने शुरुआती दो मिनट में ही नेपोली के गोलकीपर वांजा मिलिंकोविक-सैविक को परखा। इसके बाद निको ओ'रेली का हेडर क्रॉसबार के ऊपर चला गया। शुरुआती दबाव के बाद नेपोली ने धीरे-धीरे मैच में पकड़ बनाई। सिटी के पूर्व मिडफील्डर केविन डी ब्रुइन ने मेहमान टीम के अटैक को संभाला। हाफटाइम से ठीक पहले सैम बेउकेमा के हेडर को जियानलुइगी डोनारुम्मा ने शानदार सेव कर बचा लिया। 55वें मिनट में नेपोली ने बढ़त बना ली। रैसमस होजलुंड ने मार्क गुएही को पीछे छोड़ते हुए दमदार लो शॉट से डोनारुम्मा को छकाया। सिटी के कोच ने जेरेमी डोकू को मैदान में उतारा और इसका फौरन फायदा मिला। डोकू के बनाए मौके पर अय्यूब बौआदी ने 66वें मिनट में सिटी के लिए अपना पहला गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। हालांकि, 10 मिनट बाद ही नेपोली ने फिर बढ़त ले ली। लियोनार्डो स्पिनाजोला के क्रॉस पर नोआ लैंग ने शानदार वॉली मारी, जिस पर डोनारुम्मा के पास कोई मौका नहीं था।



शतरंज विश्व चैंपियनशिप : समय के दबाव में भी डटे रहे गुकेश, सिंदारोव के साथ पहला मैच ड्रॉ

जिनेवा (एजेंसी)



विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 की शुरुआत भारतीय ग्रैंडमास्टर और मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश ने ड्रॉ के साथ की। चैंपियनशिप के पहले मुकाबले में उन्होंने उज्बेकिस्तान के ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंदारोव को बराबरी पर रोक दिया। सफेद मोहरों से खेल रहे सिंदारोव के खिलाफ गुकेश ने काले मोहरों से मुकाबला किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच यह मुकाबला 38 चालों तक चला और तीन बार एक जैसी स्थिति बनने के बाद ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

बर्लिन डिफेंस में सिंदारोव की मजबूत तैयारी

मुकाबले में गुकेश ने रुई लोपेज-बर्लिन डिफेंस का सहारा लिया। सिंदारोव इस ओपनिंग के लिए अच्छी तैयारी के साथ उतरे थे। उन्होंने तेजी से चालें चलीं और बर्लिन डिफेंस की एक अलग रणनीति अपनाई। उनकी तैयारी साल 2020 में ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारुआना और वेस्ली सो के बीच खेले गए मुकाबले पर आधारित थी, जिसमें कारुआना ने सफेद मोहरों से जीत हासिल की थी। हालांकि, गुकेश ने अपनी चालों से मुकाबले को संतुलित बनाए रखने की कोशिश की। सिंदारोव की 13वीं चाल एनई4 के जवाब में गुकेश ने बीडी7 खेला। इसके बाद सिंदारोव ने 14वीं चाल में सी4 खेली, जिस पर गुकेश ने ए5 से जवाब दिया।

गुकेश पर बना समय का दबाव

मुकाबले के दौरान गुकेश को समय के दबाव का सामना करना पड़ा। 17वीं चाल पर सिंदारोव के बी3 खेलने के बाद गुकेश ने बीबी4 की चाल चली। इस चाल से उन्होंने डी2 पर मौजूद सफेद खिलाड़ी के रूक को निशाना बनाया। इस चाल को चलने में गुकेश ने करीब 36 मिनट लगाए। इसके बाद 22वीं चाल पर सिंदारोव ने 20 मिनट सोचने के बाद एनई1 खेला। दोनों खिलाड़ियों के बीच इसके बाद कई मोहरों की अदला-बदली हुई।

आखिरकार मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इस दौरान सिंदारोव को गलत तरीके से ड्रॉ का दावा करने के कारण घड़ी पर समय का जुर्माना भी झेलना पड़ा। मुकाबले के दौरान कुछ समय के लिए गुकेश के पास एक अतिरिक्त प्यादा था, लेकिन सफेद मोहरों की सक्रिय स्थिति के कारण सिंदारोव ने बराबरी बनाए रखी। दोनों खिलाड़ियों ने काफी सटीक खेल दिखाया। हालांकि, सफेद मोहरों से खेलते हुए सिंदारोव ने गुकेश पर हल्का दबाव जरूर बनाया। अब दोनों खिलाड़ियों के बीच अगला मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। इस बार गुकेश सफेद मोहरों के साथ उतरेंगे। ऐसे में उनके पास अपनी तैयारी और रणनीति दिखाने का अच्छा मौका होगा।

आईपीएल 2027 की नीलामी के लिए 1,220 खिलाड़ियों के नाम दर्ज, बीसीसीआई ने दी जानकारी

नई दिल्ली (एजेंसी)



भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बताया है कि आईपीएल 2027 के लिए होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी के लिए ऑक्शन रजिस्टर में कुल 1,220 खिलाड़ियों के नाम दर्ज हैं। इसमें 939 भारतीय खिलाड़ी हैं, जबकि 281 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं।

विदेशी खिलाड़ी 17 अलग-अलग देशों से संबंध रखते हैं। आईपीएल 2027 के लिए होने वाली नीलामी से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने 184 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया है या चुन लिया है। नीलामी में ज्यादा से ज्यादा 66 स्लॉट्स भरे जा सकते हैं, जिनमें 25 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। रजिस्टर में 184 कैप्ड प्लेयर्स, 994 अनकैप्ड प्लेयर्स और एसोसिएट नेशंस के 42 प्लेयर्स शामिल हैं। अनकैप्ड प्लेयर्स में 925 इंडियन हैं, जिनमें 127 ऐसे हैं जो पिछले आईपीएल सीजन में खेल चुके हैं। ओवरसीज रजिस्ट्रेशन में ऑस्ट्रेलिया 53 खिलाड़ियों के साथ सबसे आगे है। उसके बाद साउथ अफ्रीका (40), वेस्टइंडीज (36), न्यूजीलैंड (25) और अफगानिस्तान (23) हैं। इस लिस्ट में एसोसिएट नेशंस के खिलाड़ी भी हैं, जिसमें यूएसए ने 13 रजिस्ट्रेशन किए हैं। उसके बाद यूएई और नेपाल ने 10-10 रजिस्ट्रेशन किए हैं। फ्रेंचाइजी अब ऑक्शन रजिस्टर से उन खिलाड़ियों के नाम सबमिट करेंगी, जिन्हें वे फाइनल प्लेयर पूल में शामिल करना चाहते हैं।

'डफी एक 'क्लासी बॉलर', हम उन्हें लेकर चिंतित नहीं': मैट हेनरी

नई दिल्ली (एजेंसी) भारत के साथ वेलिंगटन में खेले गए पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी पूरी तरह प्रभावहीन रहे थे। डफी ने 33 ओवर में 201 रन लुटाकर महज 1 विकेट लिया था। इस प्रदर्शन के बाद आलोचना का शिकार हुए डफी को टीम के सीनियर तेज गेंदबाज मैट हेनरी का समर्थन मिला है। मैट हेनरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'जैकब डफी एक 'क्लासी बॉलर' हैं। उन्होंने इतने सालों में दिखाया है कि वह पूरी तरह से टीम के बारे में सोचते हैं। जब हम सुझाव देते हैं कि शायद हम यहां एक प्लान बनाएं, तो वह अपने निजी आंकड़ों के बारे में चिंतित नहीं होते।' हेनरी ने कहा, 'डफी की स्किल पर कोई सवाल नहीं है। हमारे लिए, ऐसे पल थे जब हमें किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो एक अलग प्लान आजमा सके, और वह ऐसा करने के लिए तैयार था। मुझे लगता है कि शायद यही टीम की क्वालिटी है। यह नतीजे की चिंता नहीं है, बल्कि यह है कि आप गेम पर कैसे असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में यह दिखा है, उसके ऐसे माइंडसेट की वजह से उसके असर मैच जिताने वाले रहे हैं। इसलिए हम उसे लेकर ज्यादा परेशान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बेसिन रिजर्व पर गेंद बहुत कम स्लिप तक जा पाती थी। इस वजह से डफी को आंकड़ों की परवाह किए बिना बाउंसर फेंकने के लिए कहा गया था और उन्होंने यही किया। जैकब डफी का नाम न्यूजीलैंड के लिए तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन गेंदबाजों के तौर पर लिया जाता है।



'15 साल का लड़का 28 छक्के नहीं मार सकता': तनवीर अहमद

दोहा (एजेंसी)



जहां एक तरफ पूरी दुनिया महज 15 साल के भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक और तूफानी पारी का लोहा मान रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी दिग्गज अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें वैभव की यह विस्फोटक बल्लेबाजी पच नहीं रही है और जलन के मारे वे इस युवा स्टार को लेकर लगातार गलत और बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने एक बार फिर भारत और भारतीय क्रिकेटरों के खिलाफ जहर उगलते हुए वैभव की उम्र पर सवाल खड़े किए हैं।

भारत-पाकिस्तान की संभावित फाइनल से पहले बौखलाया पाकिस्तान

दोहा में खेले जा रहे एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा, लेकिन इसके झटके पाकिस्तान में महसूस किए जा रहे हैं। दरअसल, ग्रुप स्टेज में भारत को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पाकिस्तान-ए टीम को अब डर सता रहा है कि कहीं फाइनल में उसका सामना फिर से प्रचंड फॉर्म में चल रही इंडिया-ए और वैभव सूर्यवंशी से न हो जाए। वैभव की इसी आक्रामक बल्लेबाजी से घबराए तनवीर अहमद ने उनकी उम्र को लेकर विवादित बयान दिया है।

वैभव की उम्र को लेकर क्या बोले तनवीर अहमद?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक टीवी चैनल के वीडियो में तनवीर अहमद ने वैभव की काबिलियत पर संदेह जताते हुए कहा, 'वह 15 साल का तो बिल्कुल नहीं है, कम से कम 20-21 साल का है। उसकी वजह यह है कि कोई कितना भी बड़ा टैलेंट क्यों न हो, 15 साल का बच्चा ऐसे 28 छक्के नहीं मार सकता।

इतनी कम उम्र के बच्चे का बेस इतना मजबूत नहीं हो सकता और न ही उसकी बाजुओं में इतनी जान होती है। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि वह 15 साल का है। हो सकता है 20 साल का हो, हो सकता है 21 साल का हो।' इस पर एंकर बोलता है कि कलाई का टेस्ट करा लिया जाए? इस पर तनवरी कहते हैं- करा लें, लेकिन मैं नहीं मानता वह 15 साल का है। बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने मंगलवार को यूएई के खिलाफ महज 53 गेंदों में 204 रनों की अकल्पनीय पारी खेली थी। इस पारी के दौरान उन्होंने 28 गगनचुंबी छक्के और सात चौके जड़े, जिसकी बदौलत इंडिया-ए ने 250 रनों के विशाल लक्ष्य को सिर्फ 14.2 ओवर में ही हासिल कर सेमीफाइनल का टिकट कटाया।

आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी : श्रीलंका बनी चैंपियन, आयरलैंड को 6 विकेट से हराया

अजमान (एजेंसी)



श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड को 6 विकेट से हराकर आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण था। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम 19.3 ओवर में 96 रन पर सिमट गई। आयरलैंड की तरफ से अलाना डलजेल ने सबसे ज्यादा 24 रन बनाए। इसके अलावा, एमी हंटर ने 10, लुसी लिटिल ने 15 और जॉर्जिना डिम्सी ने 13 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से सत्या संदीपनी ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में मात्र 13 रन देकर 4 विकेट लिए।

इसके अलावा, चेथना, सुगंदीका, निमाशा और कविशा ने 1-1 विकेट लिए। श्रीलंका ने 97 रन का लक्ष्य 12.4 ओवर में 4 विकेट खोकर 99 रन बनाकर हासिल कर लिया। 44 गेंद शेष रहते मिली 6 विकेट की बड़ी जीत के साथ श्रीलंका टूर्नामेंट की चैंपियन बनी। श्रीलंका की तरफ से इमेशा दुलानी ने 25 गेंदों पर नाबाद 44 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके अलावा, संजना काविंदी ने 22 गेंदों पर 25 रन बनाए। कप्तान हर्षिता समरविक्रमा शून्य और विकेटकीपर कौशानी 3 रन बनाकर आउट हुईं। आयरलैंड के लिए किया मैक्काथी और कारा मर्रे ने 2-2 विकेट लिए। श्रीलंका की विश्मी गुणारत्ने प्लेयर ऑफ द सीरीज और सत्या संदीपनी प्लेयर ऑफ द मैच रहीं। आईसीसी ने नवंबर 2025 में दुनिया भर में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने और उभरती टीमों को उच्च-स्तरीय अनुभव देने के लिए इस टी20 टूर्नामेंट की शुरुआत की थी।

छठ पूजा की भक्ति में डूबीं मौनी रॉय, पटना पहुंचकर बोलीं- 'यह सिर्फ पर्व नहीं, एक एहसास है'



अभिनेत्री मौनी रॉय हाल ही में बिहार की राजधानी पटना पहुंचीं, जहां उन्होंने छठ पूजा की भक्ति और परंपराओं को करीब से देखा। इस दौरान वह शहर की खूबसूरत गलियों में घूमीं और छठ के दौरान लोगों की आस्था और उत्साह को महसूस किया। पटना में बिताए इन खास पलों की झलक मौनी ने सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने बताया कि इस शहर की संस्कृति, लोगों का प्यार और छठ पूजा का आध्यात्मिक माहौल उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। मौनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह पटना की सड़कों पर घूमती और छठ पूजा से जुड़े नजारे देखती नजर आ रही हैं। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, 'पटना, तुम वाकई बहुत खास रहे। शहर की खूबसूरत गलियों में घूमने से लेकर छठ पूजा की भक्ति, परंपराओं और रौनक को देखने तक, यहां का हर पल यादगार अनुभव रहा। हमें यहां का हर पल बहुत पसंद आया। इस खूबसूरत शहर की असली पहचान को करीब से महसूस किया। अब यहां से ढेर सारी यादें लेकर जा रहे हैं। पटना, फिर मुलाकात होगी।' इस दौरान मौनी ने छठ पूजा के आध्यात्मिक महत्व पर भी बात की। वीडियो में वह देवी मां तारा की प्रतिमा के सामने खड़ी नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा, 'जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि ये देवी मां तारा हैं। पटना में छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि पूजा है। यह एक भावना और एहसास है। मेरे हिसाब से यह बहुत आध्यात्मिक और पवित्र है।' पटना दौरे के दौरान मौनी गोल्डन रंग की खूबसूरत साड़ी में नजर आईं। वीडियो में वह देवी मां तारा की प्रतिमा के सामने खड़े होकर छठ पूजा के महत्व के बारे में बताती भी दिखाई दीं। बता दें कि छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित प्रमुख पर्व है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में इसे बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में व्रती कठिन नियमों का पालन करते हुए उपवास रखते हैं और डूबते तथा उगते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। **(एजेंसी)**

'मैं प्रॉब्लेमेटिक नहीं बनना चाहती', फैमिली वीक में नहीं जाएंगी स्काउट की गर्लफ्रेंड काश्वी

रियलिटी शो 'बिग बॉस-20' कंटेस्टेंट स्काउट की गर्लफ्रेंड काश्वी हीरानंदानी ने साफ कर दिया है कि वो शो के फैमिली वीक में हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वो अब और किसी मुसीबत से दूर रहना चाहती हैं और बस शो को देखकर एंजॉय करना चाहती हैं। काश्वी ने यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने छूटे हुए एपिसोड देखने के बारे में बात की। इस दौरान एक फैन ने उनसे सवाल पूछा कि क्या वो फैमिली वीक के लिए बिग बॉस के घर में एंट्री लेंगी। इस सवाल का जवाब देते हुए काश्वी ने कहा कि उन्होंने पहले ही इस सेगमेंट का हिस्स बनने से मना कर दिया है और कहा कि वो अब और कोई मुसीबत पैदा नहीं करना चाहती और ना ही किसी मुसीबत में पड़ना चाहती हैं। उन्होंने कहा, मैंने फैमिली वीक में जाने से पहले ही मना कर दिया है। मैं प्रॉब्लेमेटिक नहीं बनना चाहती। मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैं बस चिल करना चाहती हूं। मैं बस आप सबके साथ शो देखना और उसे एंजॉय करना चाहती हूं। उन्होंने आगे कहा, इस वजह से मैंने शो में जाने से पहले ही मना कर दिया है। मुझे लगता है कि उनके माता-पिता, भाई रोहित या नियो में से किसी एक को वहां पर जाना चाहिए। मैं नहीं जा रही हूं। मेरा मानना है कि स्काउट को जो भी मैसेज देना है, वो कोई भी अच्छे से दे सकता है और उसके लिए उनका जाना जरूरी नहीं है। काश्वी ने बताया कि पिछली बार वह उनके माता-पिता की मर्जी के खिलाफ बिग बॉस में गई थीं। उन्होंने कहा, शो से वापस आने के बाद, मैंने माता-पिता को बताया था। अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करना चाहतीं और किसी भी तरह शो का हिस्सा नहीं बनना चाहतीं। काश्वी का ये फैसला बिग बॉस 20 में स्काउट और लव गिल को लेकर हुए विवाद के बाद आया है। शो के दौरान उन्होंने दोनों के बीच के रिश्ते को लेकर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की थी और स्काउट को लव के साथ ज्यादा नजदीकी को लेकर चेतावनी भी दी थी। काश्वी ने खास तौर पर दोनों के ऑन स्क्रीन बातचीत पर सवाल उठाए थे, जिसमें एक-दूसरे को मसाज देना भी शामिल था। उन्होंने कहा था कि उन्हें ये बर्ताव नेशनल टेलीविजन के लिए सही नहीं लगा। स्काउट और लव के बीच का रिश्ता तब से दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, दोनों से बार-बार उनकी नजदीकी और क्या उनके बीच कोई अट्रैक्शन है, इस बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। दोनों ने ही रोमांटिक रिश्ते में होने से इनकार किया है। **(एजेंसी)**





मैं सड़क निर्माण के खिलाफ नहीं, विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना सही नहीं : सोहा अली खान

मुंबई में वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई को लेकर अभिनेत्री सोहा अली खान ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर नहीं चुकाई जानी चाहिए। मंगलवार को सोहा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने नाना-नानी पार्क से जुड़ी पुरानी यादों के साथ पेड़ों की कटाई और इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के बारे में बात की। सोहा ने कहा, 'करीब 25 साल पहले नाना-नानी पार्क की जगह सिर्फ कचरे का ढेर हुआ करता था। बाद में वर्सोवा के स्थानीय लोगों ने मिलकर इस जगह की सफाई की, यहां पेड़ लगाए और हर गर्मी में उन्हें पानी देकर उनकी देखभाल की। लोगों की मेहनत से यह जगह धीरे-धीरे हरे-भरे पार्क में बदल गई, लेकिन पिछले हफ्ते बीएमसी ने अचानक यहां पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसकी वजह नए वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए इंटरचेंज बनाने की योजना है।' मुंबई में ट्रैफिक की समस्या को लेकर सोहा ने वीडियो में कहा, 'शहर को सड़कों की जरूरत है और यहां ट्रैफिक की परेशानी भी रियल है। वर्सोवा-मड ब्रिज प्रोजेक्ट से 22 किलोमीटर का सफर घटकर सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह जाएगा। हाईकोर्ट ने भी इस प्रोजेक्ट को जनहित से जुड़ा जरूरी काम बताया था और इसके लिए बीएमसी को 1,237 मैंग्रोव हटाने की अनुमति दी थी।' उन्होंने कहा, 'पेड़ों की कटाई के पक्ष में यह तर्क दिया जा सकता है कि इससे लोगों का समय बचेगा, ईंधन की खपत कम होगी और उनका सफर आसान होगा, लेकिन नाना-नानी पार्क के मामले में 184 पेड़ों को काटने और 164 पेड़ों को हटाने की योजना है। इस पार्क के कुल 348 पेड़ों पर असर पड़ेगा, जिसे स्थानीय लोगों ने अपनी मेहनत से तैयार किया था।' सोहा ने कहा, 'स्थानीय निवासी इस कार्रवाई का कड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीएमसी का तर्क है कि जिस जमीन पर पार्क मौजूद है, वह पहले से ही सड़क निर्माण के लिए आरक्षित थी। पिछले 25 साल में इस जमीन का इस्तेमाल नहीं किया गया।' पेड़ों को दूसरी जगह लगाने की योजना पर सवाल उठाते हुए सोहा ने मुंबई में हुए पिछले बड़े अदालती ऑडिट का जिक्र किया और कहा, 'इस ऑडिट में सामने आया था कि दूसरी जगह लगाए गए आधे से ज्यादा पेड़ या तो मर चुके थे या उनकी हालत खराब थी। ऐसे में पेड़ों को दूसरी जगह लगाने का विकल्प भी पर्यावरण को बचाने की पूरी गारंटी नहीं देता। मैंग्रोव मुंबई के लिए प्राकृतिक सुरक्षा दीवार की तरह काम करते हैं। **(एजेंसी)**



अर्जुन कपूर : गुरु पर्व पर किसके साथ नजर आए अभिनेता? सोशल मीडिया पर वायरल सेल्फी ने दी डेटिंग रूमर्स को हवा

क्या मलाइका अरोड़ा के बाद अर्जुन कपूर की जिंदगी में कोई आ गया है? अभिनेता की निजी जिंदगी को लेकर कुछ यही सवाल किए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत उनकी एक हालिया वायरल तस्वीर से हो रही है। यह गुरु पर्व के अवसर की फोटो है। अर्जुन कपूर की यह तस्वीर साहिबा बाली ने साझा की है। साहिबा एक चर्चित कंटेंट क्रिएटर हैं। उन्होंने प्रकाशोत्सव के अवसर पर अर्जुन कपूर के साथ एक सेल्फी शेयर की है। इसमें दोनों मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। साहिबा ने जो कैप्शन लिखा है, उसने लोगों का ध्यान खींचा है। साहिबा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह सेल्फी शेयर की है। इसके साथ लिखा है, 'मैंने इनका आधा प्रसाद भी खा लिया। गुरु पर्व की शुभकामनाएं'। यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक तो अर्जुन के साथ सेल्फी ऊपर से साहिबा का कैप्शन..दोनों ही चीजों के बाद नेटिजंस सवाल कर रहे हैं कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? अर्जुन और साहिबा की यह फोटो रेडिट पर भी एक यूजर ने साझा की है। इस पर अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने इस फोटो को इन दोनों के रिश्ते की सॉफ्ट लॉन्चिंग कहा है। वहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया है। एक यूजर ने लिखा है, 'यह चर्चा में बने रहने का इन दोनों का तरीका है'। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है, जब अर्जुन कपूर का नाम साहिबा से जोड़ा जा रहा है। पहली बार जुलाई में इन्हें लेकर चर्चा शुरू हुई थी। दरअसल, 19 जुलाई को दोनों लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला देखने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों साथ बैठे नजर आए थे। इनकी तस्वीर तब भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। **(एजेंसी)**

फॉक्सकॉन इंडिया पर लगा स्थानीय वेंडर्स का देरी से भुगतान का आरोप, 143 करोड़ रुपए की दिवालिया याचिका दायर

नई दिल्ली (एजेंसी)

ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप की भारतीय इकाई पर कई स्थानीय वेंडर्स को भुगतान में देरी करने के आरोप लगे हैं। इस बीच, कंपनी के एक वेंडर ने लगभग 143 करोड़ रुपए (1.53 करोड़ डॉलर) के बकाया भुगतान की वसूली के लिए दिवालिया याचिका दायर की है।

यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, फॉक्सकॉन की बेंगलुरु स्थित फैक्ट्री में कर्मचारियों के लिए डॉर्मिटरी आवास की सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी बीसीडी एम्प्रासा एलएलपी ने चेन्नई स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का रुख किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने फॉक्सकॉन होन हाई टेक्नोलॉजी इंडिया मेगा डेवलपमेंट



प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुए अनुबंध के तहत किराए और बिजली-पानी सहित अन्य उपयोगिता शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। ब्लूमबर्ग द्वारा देखे गए अदालती दस्तावेजों के अनुसार, वेंडर लगभग 143 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है। इसमें बकाया राशि, ब्याज, सेवा शुल्क और 8 जुलाई तक की गणना के अनुसार हर्जाना शामिल है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आईफोन असेंबल करने वाली फॉक्सकॉन की भारतीय इकाई के करीब आधा दर्जन वेंडर भुगतान में देरी का सामना कर रहे हैं।

इनमें से कम से कम चार वेंडर कथित तौर पर कई महीनों से लेकर एक साल से अधिक समय से अपने बकाये के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कई कंपनियां बेंगलुरु स्थित फॉक्सकॉन के संयंत्र में निर्माण और बुनियादी ढांचे से जुड़े काम में लगी हुई थीं। दस्तावेजों के अनुसार, अप्रैल 2024 में हुए एक समझौते के तहत बीसीडी एम्प्रासा ने प्लांट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए 700 आवासीय इकाइयां लीज पर ली थीं।

इसमें यह प्रावधान था कि आवासीय इकाइयों में कर्मचारियों के रहने या नहीं रहने की स्थिति में भी किराए का भुगतान करना होगा। साथ ही, इस समझौते की लॉक-इन अवधि जुलाई 2026 तक थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फॉक्सकॉन ने मई 2025 से देय इनवॉइस का भुगतान नहीं किया। ब्लूमबर्ग ने बीसीडी एम्प्रासा के एक बयान का हवाला देते हुए कहा, इन चूकों के कारण कंपनी को गंभीर वित्तीय नुकसान और काफी व्यावसायिक क्षति हुई है।

त्योहारी सीजन में क्रेडिट कार्ड से खर्च में आई तेजी, अक्टूबर में 20 प्रतिशत बढ़कर 2.45 लाख करोड़ रुपए हुआ

नई दिल्ली (एजेंसी)

दीपावली से पहले त्योहारी सीजन की खरीदारी में तेजी आने के बीच अक्टूबर में भारत में क्रेडिट कार्ड से खर्च में तेज वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान कुल लेनदेन का मूल्य मासिक आधार पर करीब 20 प्रतिशत बढ़कर 2.45 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया।

सितंबर में क्रेडिट कार्ड से लेनदेन 2.04 लाख करोड़ रुपए का रहा था। वहीं, अक्टूबर में हुआ खर्च पिछले साल के इसी महीने की तुलना में भी 14.4 प्रतिशत अधिक रहा, जो उपभोक्ता खर्च में लगातार मजबूती को दर्शाता है। बैंकों ने अक्टूबर में कुल मिलाकर 14 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए, जिससे उद्योग में सक्रिय क्रेडिट कार्ड की कुल संख्या बढ़कर 12.67 करोड़ हो गई। सितंबर में यह संख्या 12.53 करोड़ थी। डिजिटल माध्यमों से खरीदारी का दबदबा लगातार बना हुआ है। ऑनलाइन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1.54 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ, जो कुल क्रेडिट कार्ड खर्च का करीब 63 प्रतिशत है।

वहीं, पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) के माध्यम से लेनदेन 90,562 करोड़ रुपए रहा। देश के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता एचडीएफसी बैंक ने खर्च के मामले में अपनी अग्रणी स्थिति बरकरार रखी। बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से महीने के दौरान 70,115 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ, जो पिछले महीने की तुलना में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

स्टॉक कमी और सावों की मांग से देशी घी 10,875 रुपए टिन के पार, SMP में भी रिकॉर्ड तेजी

जयपुर (एजेंसी)

शादियों के सीजन (सावों) की शुरुआत और कैरी-फॉरवर्ड स्टॉक की भारी कमी ने डेयरी कमोडिटी बाजार का गणित बिगाड़ दिया है। दिवाली के बाद से ही देशी घी और स्किम्ड मिल्क पाउडर की कीमतों में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। थोक बाजार में इन दोनों ही उत्पादों के भाव 20 से 30 रुपए प्रति किलो तक उछल चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि फ्लश सीजन के चलते डेयरी प्लांटों में तरल दूध (लिक्विड मिल्क) की दैनिक आपूर्ति बढ़कर एक करोड़ लीटर के स्तर पर पहुंच गई है, इसके बावजूद कीमतों में



नरमी के बजाय तेजी हावी है। बाजार विश्लेषकों और डेयरी कारोबारियों के अनुसार, कीमतों में इस उछाल के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं।

पहला, छठ पूजा के तुरंत बाद देशभर में वैवाहिक सीजन शुरू होने से बल्क खरीदारों, कैटरर्स और मिठाई निर्माताओं की तरफ से देशी घी की जबरदस्त मांग निकल रही है। दूसरा, पिछले सीजन का बचा हुआ स्टॉक (बफर स्टॉक) लगभग समाप्त हो चुका है, जिससे बाजार में 'स्टॉक तंगी' की स्थिति बनी हुई है। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इस बार स्किम्ड मिल्क पाउडर की दरें काफी ऊंची बोली जा रही हैं। वैश्विक बाजार में भारतीय दूध पाउडर की निर्यात मांग (एक्सपोर्ट डिमांड) मजबूत होने से घरेलू प्लांटों में आने वाला अतिरिक्त दूध सीधे पाउडर और बटर में कन्वर्ट हो रहा है। यही कारण है कि एक करोड़ लीटर प्रतिदिन की भारी आवक के बावजूद घरेलू बाजार में सप्लाई का दबाव कम नहीं हो पा रहा है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक, उत्पादन 69 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली (एजेंसी)

भारत दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखे हुए है। 2014-15 में देश का दूध उत्पादन 146.31 मिलियन टन था, जो 2024-25 में 69.41% बढ़कर 247.87 मिलियन टन हो गया। यह जानकारी बुधवार को जारी एक आधिकारिक फैक्टशीट में दी गई। यह फैक्टशीट 26 नवंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय दुग्ध दिवस से पहले जारी की गई है।

भारत वैश्विक दूध उत्पादन में करीब एक-चौथाई हिस्सेदारी रखता है। पिछले एक दशक में देश का दूध उत्पादन 5.41 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से



बढ़ा है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भी 2014-15 के 319 ग्राम प्रतिदिन से 52.03 प्रतिशत बढ़कर 2024-25 में 485 ग्राम प्रतिदिन हो गई। औसत गोवंशीय दूध उत्पादकता 2014-15 में प्रति पशु प्रति वर्ष 1,640 किलोग्राम थी, जो 2024-25 में बढ़कर 2,800 किलोग्राम प्रति पशु प्रति वर्ष हो गई। इस दौरान इसमें 69 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र ने मिलकर देश के कुल दूध उत्पादन में 54.09 प्रतिशत का योगदान दिया। इसमें उत्तर प्रदेश 15.66 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रहा।

डेयरी क्षेत्र ग्रामीण इलाकों के 8.5 करोड़ परिवारों की आजीविका का आधार है। डेयरी फार्मिंग से जुड़े कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत है। फैक्टशीट में कहा गया कि दूध उत्पादन में 5.41% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी गहरा संबंध है। डेयरी क्षेत्र 8.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को आजीविका प्रदान करता है, जबकि भारत के डेयरी फार्मिंग कार्यबल में करीब 70% महिलाएं शामिल हैं। हर साल 26 नवंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उन्हें भारत की श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भारत के डेयरी सहकारी नेटवर्क में 22 दुग्ध महासंघ, 241 जिला सहकारी दुग्ध संघ, 28 विपणन डेयरियां और 25 दुग्ध उत्पादक संगठन (एमपीओ) शामिल हैं।

यह नेटवर्क करीब 2.45 लाख गांवों और 1.65 करोड़ डेयरी किसानों को कवर करता है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड डेयरी सर्विसेज (एनडीडीबी-डीएस), जो दुग्ध उत्पादक संगठनों (एमपीओ) के गठन और उनके संचालन को सुविधाजनक बनाता है, ने 31 अक्टूबर 2026 तक सफलतापूर्वक 25 एमपीओ स्थापित किए हैं।